

भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति... सज गया दोस्ती का मंच

पुतिन-मोदी मिलन में आज डिफेंस डील का नया अध्याय



नई दिल्ली, एजेंसी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंच गए हैं। पुतिन देर रात करीब 3 बजे नई दिल्ली पहुंचे। रेड कार्पेट और गाई ऑफ ऑनर के बाद पुतिन का काफिला आईटीसी मौर्या होटल पहुंचा जहां उन्हें ठहराया गया है। ब्रिक्स से पहले आज प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बैठक होगी। इसमें Su-57 फाइटर जेट और अपडेटेड ब्रह्मोस समेत कई डिफेंस डील पर चर्चा हो सकती है। फाइटर जेट की बिन्नी के साथ भारत में इसके उत्पादन और जरूरी तकनीक साझा करने की पेशकश रूस पहले ही कर चुका है। भारत चाहता है कि इस डील से उसे ऐसी तकनीक मिले, जिसका इस्तेमाल आगे स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने में भी किया जा सके।

करीब एक हफ्ते के भीतर मोदी और पुतिन की ये दूसरी मुलाकात होगी। इससे पहले 31 अगस्त को बिश्केक में एससीओ समिट के दौरान दोनों नेताओं की

■ **Su-57 के प्रोडक्शन और जरूरी तकनीक साझा करने पर सहमति संभव**

बातचीत हुई थी। लेकिन इस बार इस मुलाकात का एजेंडा कहीं बड़ा है। भारत-रूस के रिश्ते सिर्फ रक्षा तक सीमित नहीं हैं। ऊर्जा, परमाणु सहयोग, ट्रेड, निवेश, स्पेस और नई टेक्नोलॉजी तक दोनों देश साझेदारी बढ़ा रहे हैं। पुतिन के भारत दौरे से पहले क्रैमलिन ने साफ कर दिया है कि दोनों नेता सबसे पहले द्विपक्षीय एजेंडे पर बात करेंगे।

जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी वह है सुखोई-57 फिफ्थ जेन फाइटर जेट। रूस ने पहली बार साफ संकेत दिया है कि भारत को Su-57 बेचने का मुद्दा मोदी-पुतिन की बैठक के एजेंडे में है। इसके अलावा भारत के साथ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी साझा करने की संभावनाओं पर भी बातचीत चल रही है। रूस ने कहा कि हर देश अपनी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी को अपने पास रखना चाहता है, लेकिन भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को देखते हुए रूस टेक्नोलॉजी साझा करने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है।

नए परमाणु ऊर्जा प्लांट

रूस भारत में नए परमाणु ऊर्जा प्लांट लगाने को लेकर आगे की बातचीत का भी इंतजार कर रहा है। यानी न्यूक्लियर एनर्जी में नए प्रोजेक्ट्स पर बड़ा रास्ता खुल सकता है। इसके साथ ही रक्षा सहयोग में मौजूदा प्रतिबद्धताएं भी अहम होंगे। एस-400 की बाकी डिलीवरी और भारत-रूस के दूसरे संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट पर भी बातचीत संभव है। तीसरा बड़ा मुद्दा है व्यापार और आर्थिक साझेदारी। दोनों देश व्यापार बढ़ाने, निवेश बढ़ाने और भारतीय कंपनियों की रूस में तथा रूसी कंपनियों की भारत में मौजूदगी मजबूत करने पर बात करेंगे।

दिल्ली में कम्युनिटी सेंटर के पास फायरिंग, 2 युवक घायल

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाना क्षेत्र में कड़कड़हूमा कम्युनिटी सेंटर के पास फायरिंग की घटना में दो युवक गोली लगने से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल दोनों युवक हाईपर कैफ में पार्टी करके घर लौट रहे थे। घायलों की पहचान मुरादनगर निवासी अफसर और सीलमपुर निवासी इरशाद के रूप में हुई है।

शिवपुरी में महिलाओं का गुस्सा बोलतें तोड़कर बहाई शराब

शिवपुरी। यहाँ शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और शराब की बोतलें लाकर थाने के बाहर बहा दीं। पुलिस ने अलग-अलग थानों में इनके खिलाफ केस दर्ज किया है। जिले के अमोलपढ़ा, मनपुरा और थरखेड़ा में शराब की दुकानें बंद कराने को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने सरकारी दुकानों से बीयर और शराब की पेटियां बाहर निकालीं और लाटियों से तोड़ दीं महिलाएं शराब की बोतलें लेकर शौती थाने भी पहुंचीं।

बरायठा के जंगल में मुठभेड़, पैर में लगी गोली

शार्ट एनकाउंटर के बाद शराब कांड का मुख्य आरोपी लखेरा गिरफ्तार

सागर। पुलिस ने जहरीली शराब मामले में आज सुबह मुख्य आरोपी रवि लखेरा का शॉर्ट एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार किया है। बरायठा के जंगल में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान रवि लखेरा के पैर में गोली लगी। पुलिस घायल आरोपी को इलाज के लिए बंडा अस्पताल लेकर पहुंची है। रवि पर 20 हजार का इनाम था।

जहरीली शराब पीने से अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती 3 और मरीजों ने दम तोड़ा था। हालांकि, प्रशासन 16 मौतों की ही पुष्टि कर रहा है। इससे पहले प्रशासन ने गुरुवार को 3 आरोपियों के 5 मकानों के अवैध हिस्सों पर बलडोजर चलाया था। इनमें आरोपी मनीष लोधी, करणी सेना के संभागीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राजपूत और आशीष साहू के



निर्माण शामिल हैं। वहीं, पुलिस ने अब तक 33 लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें रवि लखेरा समेत 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। रवि लखेरा मूल रूप से छतरपुर जिले के महोबा का रहने वाला है। फिलहाल वह उत्तर प्रदेश के ललितपुर की गंगापुरम कॉलोनी में रहता है। पुलिस के मुताबिक वह अंतरराज्यीय शराब तस्क़र है। उसके खिलाफ मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश समेत अन्य जगहों पर करीब 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले आबकारी एक्ट से जुड़े हैं।

नेतन्याहू बोले- मिशन पूरा, हैप्पी न्यू ईयर

इजराइल ने हिजबुल्लाह की दो किमी लंबी सुरंग उड़ाई

बेरुत, एजेंसी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग को ब्लास्ट कर तबाह कर दिया। यह विस्फोट इतना तेज था कि इलाके में 4.1 तीव्रता वाले भूकंप जैसे झटके महसूस किए गए। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक, धमाके से आसपास के इलाकों में जमीन हिलने लगी। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन

नेतन्याहू ने कहा, 'मिशन पूरा हुआ। हैप्पी न्यू ईयर।' इजराइली सेना के मुताबिक, सुरंग में ईरान में बने कई रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन रखे थे। यहां मशीनगन, एंटी-टैंक मिसाइल और सैकड़ों बारूदी सुरंगें व विस्फोटक भी मिले। सेना ने बताया कि इस परिसर में हिजबुल्लाह की 'बद' यूनिट का कमांड सेंटर भी था।

एमपी में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 12 जिलों में अलर्ट

केदारनाथ में बादल फटने से पैदल रास्ता बंद, दमोह में बाढ़ के हालात

नई दिल्ली / देहरादून / भोपाल

उत्तराखंड के केदारनाथ में आज बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड होने की खबर है। बड़े-बड़े बोल्टर गिरने से केदारनाथ पैदल मार्ग बंद हो गया है। वहीं, यूपी में लगातार हो रही बारिश से गंगा-यमुना समेत 10 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। इससे 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मिर्जापुर में पुल तो फरूखाबाद में हाईवे डूब गया है। एमपी के दमोह में एहतियातन स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है।

मध्य प्रदेश में तीन दिन के ब्रेक के बाद मानसूनी सिस्टम फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग के

मुताबिक, शुक्रवार को राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। गुरुवार रात भोपाल, नर्मदापुरम और विदिशा में बारिश हुई। दमोह में बाढ़ के हालात हैं। गुरुवार रात 12 बजे से शुरू हुई तेज बारिश शुक्रवार सुबह 7 बजे तक लगातार जारी रही। करीब 7 घंटे की बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। कई घरों में 3 फीट तक पानी भर गया, जबकि कुछ इलाकों में सड़कों पर करीब 4 फीट पानी जमा हो गया। घरों में फसे लोगों को सुरक्षित निकालकर सामुदायिक भवन में पहुंचाया गया।

उधर, बिहार में 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति है, जिससे 2,360 गांवों में करीब 44 लाख लोग प्रभावित हैं।

Organised by

Host Partner

AI Innovation Partner

Knowledge Partner

elets

MPYPIL

PRIMUS PARTNERS

e gov

Department of Transport
Madhya Pradesh

भारत की भगली मोबिलिटी क्रांति का शुभारंभ

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत

पुष्पांगे पारंगे रहे वर

Vision Summit 2026

11-12 सितम्बर 2026

ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, इंदौर, मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा

MP04PA4367

नया मध्यप्रदेश

events.eletsonline.com/mpyatriparivahansummit

सीधा प्रसारण

webcast.gov.in/mp/cmevents

@Cmmadhyapradesh

@jansampark.madhyapradesh

@Cmmadhyapradesh

@jansamparkMP

jansamparkMP

26

D-11109/26

आयुष्मान भारत की टीम ने की जांच तो भी कर्मचारी ड्यूटी करते मिले, जिन्होंने अब तक नर्सिंग पाठ्यक्रम ही पूरा नहीं किया

‘आयुष्मान’ में फिर गड़बड़ी, अक्षय हॉस्पिटल में BAMS कर रहे थे गंभीर मरीजों का इलाज

भोपाल। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चार इमली स्थित अक्षय हॉस्पिटल का आयुष्मान भारत की टीम ने निरीक्षण किया तो बड़ी लापरवाही सामने आई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों, उपलब्ध चिकित्सकीय एवं नर्सिंग स्टाफ तथा आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित व्यवस्थाओं की जांच की गई। निरीक्षण में अस्पताल में गंभीर कमियों एवं अनियमितताएं पाई गई। टीम ने पाया कि अस्पताल के आईसीयू में ऐसे सामान्य मरीजों को भी भर्ती किया गया था, जिन्हें



आईसीयू में भर्ती की जरूरत ही नहीं थी। वहीं कई मरीजों की स्थिति सामान्य एवं स्थिर पाए जाने के बावजूद उन्हें आईसीयू में भर्ती पाया

गया। टीम ने अस्पताल में आयुष्मान से होने वाले भुगतान को रोक दिया है। अन्य दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं।

जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं करा सका अस्पताल

निरीक्षण के दौरान आईसीयू में भर्ती मरीजों से संबंधित दस्तावेजों एवं जांच रिपोर्टों का परीक्षण भी किया गया। इस दौरान कई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई। अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकीय एवं नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था भी निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाई गई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में बीएमएस डॉक्टर काम करते मिले। इसी प्रकार अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की संख्या निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। मानव संसाधन की उपलब्धता और उनकी क्षमता भी तय मानक से कम पाई गई। अस्पताल से जवाब पूछा तो नहीं दे सके।

मरीजों से ब्लड टेस्ट के लिए भी वसूले रुपए

आयुष्मान योजना अंतर्गत इलाज, जांच समेत सभी तरह की सुविधाएं निःशुल्क हैं। इसके बाद भी अस्पताल में निरीक्षण टीम को गंभीर गड़बड़ियां मिलीं। इलाज कराने वाले मरीजों से अस्पताल प्रबंधन ने ब्लड एवं अन्य जांचों के लिए राशि लिए जाने की स्थिति भी सामने आई। बता दें कि राज्य योजना के अंतर्गत स्पष्ट है कि निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराते समय किसी भी तरह शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस वसूली पर टीम हैरत में पड़ गई।

अस्पताल प्रबंधन को थमाया नोटिस

निरीक्षण में सामने आई गंभीर कमियों एवं अनियमितताओं के आधार पर अक्षय हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही आयुष्मान भारत निरामय योजना के अंतर्गत अस्पताल का भुगतान रोक जाने का आदेश दिया गया है तथा अन्य मरीजों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीयन पर भी रोक लगा दी गई है। आयुष्मान भारत निरामय मध्यप्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरविंद शाह ने बताया कि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप उपचार एवं सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अनावश्यक आईसीयू भर्ती, निर्धारित मानकों के अनुसार चिकित्सकीय एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता न होना व हितग्राहियों से

अनुचित राशि लेना गंभीर अनियमितताओं को दर्शाता है। अस्पताल की योजनाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों की नियमित निगरानी की जा रही है। निष्कर्षण के लिए कई अस्पतालों की सघन निगरानी की जा रही है। अस्पतालों को मानकों के अनुसार कार्य करने तथा हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अस्पताल के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पताल का भुगतान रोक दिया गया है। पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।

न्यूज विडो

क्रिस्ट के नाम पर वसूली करने निकले युवक गिरफ्तार



भोपाल। वाहन की क्रिस्ट बकाया बताकर लोगों से अवैध वसूली करने वाले दो युवकों को श्यामला हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों बिना नंबर की बाइक पर घूमकर फाइनेंस की गाड़ियां तलाशते थे। पुलिस ने बताया कि शाहजहानाबाद के उजैफ खान बाइक से स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे थे। पॉलीटेक्निक चौराहे के आगे बाइक सवार दो युवकों ने उनका पीछा किया। आगे रोका और बाइक फाइनेंस होने का हवाला देते हुए क्रिस्ट बकाया बताई। वाहन खिंचवाने की धमकी दी। डर से उजैफ ने उन्हें दो हजार रुपए दे दिए। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपियों ने श्यामला हिल्स क्षेत्र में हरियाणा निवासी जमशेद खान की बाइक को भी निशाना बनाया था। पुलिस ने सीसीटीवी फेमरों के फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की है। आरोपी तालिब खान और फरदीन खान को गिरफ्तार किया है।

टेकडी पर बैठे युवक-युवती से चाकू की नोक पर मोबाइल-जेवर लूट

भोपाल। मनुआभान की टेकरी पर गुरुवार रात एक युवक महिला मित्र के साथ बैठकर बात कर रहा था। इसी दौरान बाइक से पहुंचे तीन बदमाशों ने चाकू दिखाकर दोनों को लूट लिया। पुलिस के अनुसार एमपी नगर निवासी हर्ष शर्मा मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। तीन अज्ञात बदमाश मोबाइल, उसकी महिला मित्र के सोने के टॉपस और सोने की चेन लूट ली।

कजलीखेड़ा स्टेशन में मिला युवक का शव, पुलिस कर रही जांच

भोपाल। कजलीखेड़ा स्टेशन में मंगलवार सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान दिनेश कुमार जैन (31) निवासी कजलीखेड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

नर्मदापुरम रोड पर फिसली बेकाबू बाइक, युवक की मौत

भोपाल। नर्मदापुरम रोड पर बागसेवनिया थाने के सामने बाइक फिसलने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अभय (40) निवासी अमरावती, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। वह प्राइवेट कंपनी में काम करता था। गत 6 सितंबर की रात करीब 12 बजे वह 11 मील से अमरावती की ओर जा रहा था। बागसेवनिया थाने के सामने पहुंचने पर उसकी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में उसे गंभीर चोट आई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके।

कहा था-आरजीपीवी में नौकरी लगवा दूंगा नौकरी लगाने के नाम पर महिला सहित 15 लोगों से 18 लाख रुपए की ठगी

भोपाल। गांधी नगर पुलिस ने महिला सहित 15 लोगों की शिकायत पर तीन जालसाजों पर धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज बनाने की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आरोपियों ने आरजीपीवी में नौकरी दिलाने के नाम पर सभी पंद्रह लोगों से कुल 18 लाख रुपए की ठगी की है।

आरोपियों ने रुपए लेने के बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र और साक्षात्कार के लिए फर्जी लेटर भी जारी किए थे। पुलिस के अनुसार नुसरत आयशा पति मोहल्लान खान (30), वार्ड-नंबर-2 चाचा मोहल्ला, चांदामेटा, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा की रहने

वाली है। उन्होंने 14 अन्य पीड़ितों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत करते हुए बताया कि नसीम खान उसके साथियों ने आरजीपीवी में नौकरी दिलाने की बात कही थी। आरोपियों ने कहा था कि उनकी आरजीपीवी में अधिकारियों से पहचान है और वे आसानी से नौकरी दिलावा देंगे। उनकी बातों में आकर नुसरत आयशा सहित मानेश बुनकर, जैनब अल्फिया, दानिश सिद्दीकी, रिजवान खान, यासीन, मारूफ खान, पूजा बुनकर, नीलम बुनकर, अरविंद बुनकर, जसदीप सिंह, बेबी नाज, फरहान खान, फैजान खान और शहजाद खान ने एडवांस में रुपए दे दिए।

आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई के मामले में खुलासा

निगम के एक्शन और रिपोर्ट में गड़बड़ी 7951 को दिए नोटिस, बताए 62000

भोपाल। दोपहर मेट्रो

भोपाल नगर निगम (बीएमसी) की आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर की गई कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई निगम की एक्शन टेकन रिपोर्ट और शपथ पत्र में दर्ज आंकड़ों के बीच भारी विसंगतियां सामने आई हैं। 5 अगस्त की सुनवाई के बाद निगम अफसरों ने दावा किया था कि आवासीय इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां चलाने वाले 62,000 से अधिक मामलों की पहचान की गई है। लेकिन 15 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए तैयार किए गए शपथ पत्र में निगम ने सिर्फ 7,951 मामलों में ही रूल-11 के तहत नोटिस जारी करने की बात कही है। इतना ही नहीं, निगम के वार्ड/जोन-वार आंकड़ों को जोड़ा जाए तो कुल नोटिस की संख्या भी 7,617 ही है। आलम यह है कि अपने ही शपथ पत्र में बीएमसी ने 7,951 नोटिस की बात कही है। इस तरह नोटिस के आंकड़े में भी 334 मामलों का अंतर सामने आया है। नगर निगम का झूठ इतने पर ही खत्म नहीं हो रहा है। जिम्मेदारों ने 190 परिसर बंद करने की रिपोर्ट दी, लेकिन सील सिर्फ 7 व्यावसायिक परिसर ही किए गए। बाकी व्यापारियों ने तो स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं।



कागज पर 190 बंद, जमीन पर 7 ही

शपथ पत्र में कहा गया है कि नियम विरुद्ध इस्तेमाल के लिए 190 परिसरों को बंद और सील किया गया। हालांकि, निगम के अपने रिकॉर्ड बताते हैं कि वास्तव में सिर्फ 7 प्रतिष्ठानों को ही सील किया गया है। बाकी 183 परिसरों को व्यापारियों द्वारा स्वेच्छा से बंद करने का पंचनामा तैयार किया गया। वहीं, शपथ पत्र के दूसरे हिस्से में लिखा है कि 170 परिसर बंद किए गए थे, जिनमें से 165 परिसरों को नियम पूरा करने पर दोबारा खोलने की अनुमति दे दी गई और केवल 5 परिसर ही सील रहे।

शहर के 21 जोन में इतने नोटिस			
जोन	नोटिस संख्या	जोन	नोटिस संख्या
जोन-1:	280	जोन-11	336
जोन-2:	197	जोन-12	520
जोन-3:	242	जोन-13	619
जोन-4:	234	जोन-14	209
जोन-5:	620	जोन-15	569
जोन-6:	184	जोन-16	415
जोन-7:	348	जोन-17	440
जोन-8:	603	जोन-18	464
जोन-9:	264	जोन-19	362
जोन-10:	456	जोन-20	377
		जोन-21	212
		कुल	7617

दिखने लगीं गणेशोत्सव की खुशियां

भोपाल। दोपहर मेट्रो

गणेश उत्सव को लेकर राजधानी में तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। कई स्थानों पर पंडालों का ढांचा खड़ा हो चुका है और अब आकर्षक सजावट, विद्युत रोशनी व रंग-बिरंगे डेकोरेशन का काम शुरू हो गया है। अलग-अलग झांकी समितियां इस बार भी विशेष थीम पर पंडाल और झांकियां तैयार करने में जुटी हैं। इधर, शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की अस्थायी दुकानें सजने लगी हैं। दुकानों पर अलग-अलग आकार और स्वरूप की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। लोगों घरों में स्थापना के लिए छोटी प्रतिमाएं खरीद रहे हैं।



झांकी समितियां उत्साहित

सार्वजनिक गणेश प्रतिमाओं की स्थापना को लेकर समितियों में खासा उत्साह है। पंडालों को आकर्षक बनाने के लिए सजावटी सामग्री और लाइटिंग के साथ अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शाम के समय कई क्षेत्रों में पंडालों और प्रतिमा दुकानों की रोशनी से उत्सवी माहौल नजर आने लगा है।

पर्यूषण..पोथा जी शोभायात्रा में उमड़ी श्रद्धा

भोपाल। दोपहर मेट्रो

श्वेतांबर जैन समाज के पर्यूषण पर्व के दौरान शहर के जिनालयों में श्रद्धालु श्रद्धा-भक्ति के साथ जिनेंद्र भगवान की आराधना और आत्मसाधना में लीन हैं। व्रत-उपवास, पूजा-पाठ, सामायिक, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, प्रवचन और तप-त्याग के माध्यम से श्रद्धालु आत्मकल्याण की साधना कर रहे हैं।

प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया कि सिटी मंदिर में साध्वी रत्नत्रया श्रीजी के संघ सानिध्य में भगवान महावीर का अभिषेक और पूजा-अर्चना कर कल्पसूत्र



का वाचन हुआ। गाजे-बाजे के साथ पोथा जी की शोभायात्रा निकाली गई। साध्वी विमल प्रज्ञा श्रीजी का निरंतर उपवास साधना का 26वां उपवास रहा। तुलसी नगर जिनालय में साध्वी शील धर्मा श्रीजी के सानिध्य में प्रभु की अंगरचना की गई और

शास्त्र पोथा जी की शोभायात्रा निकली। महिलाओं ने भजनों से संयम की अनुमोदना की। साध्वी ने विचारों की पवित्रता और इच्छाओं पर नियंत्रण को आत्मकल्याण का मार्ग बताया। शनिवार को विभिन्न मंदिरों में प्रभु महावीर महोत्सव मनेगा।

केंद्र सरकार के आदेश के बाद भी संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप

रियाज मंजिल शत्रु संपत्ति, नवाब परिवार की जमीनों पर सवाल



2024 को जारी प्रमाण पत्र में कोहेफजा की रियाज मंजिल, खसरा नंबर 42 को शत्रु संपत्ति घोषित किया था। यह संपत्ति नवाब

हमीदुल्लाह खान की दूसरी पत्नी आफताब जहां बेगम से संबंधित बताई गई है, जो पाकिस्तान की नागरिक थीं।

अग्निहोत्री ने पूछा-जब यह शत्रु संपत्ति घोषित, तब सरकार के कब्जे में लेने के लिए क्या किया

अग्निहोत्री का कहना है कि संपत्ति शत्रु घोषित होने के बावजूद इसे सरकार के कब्जे में लेने के लिए अब तक क्या कार्रवाई हुई, यह स्पष्ट नहीं है। ज्ञापन में 21 दिसंबर 2021 को शत्रु संपत्ति अभिरक्षक कार्यालय मुंबई की ओर से कलेक्टर भोपाल को भेजे गए पत्र का भी हवाला दिया गया है। इसमें नवाब परिवार की कुछ संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था, जबकि कुछ संपत्तियां जांच के लिए लंबित रखी गई थीं। अग्निहोत्री ने सवाल उठाया है कि चार साल बाद भी घोषित संपत्तियों को सरकार के कब्जे में लेने की कार्रवाई

क्यों नहीं हुई। साथ ही जांच में चल रही संपत्तियों की खरीद-बिक्री या उनके हस्तांतरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, इसकी जानकारी भी मांगी गई है। ज्ञापन में बेहटा की 30 एकड़ 55 डिसमिल जमीन का मामला भी उठाया गया है। वर्ष 1959 के खसरे का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि आफताब जहां बेगम के नाम बेहटा में करीब 65.4 एकड़ और बोरबन में 102 एकड़, जमीन दर्ज थी। अग्निहोत्री ने इन जमीनों की भी जांच कर शत्रु संपत्ति घोषित करने की मांग की है।

डाक विभाग की हिंदी सलाहकार समिति में राजेश सिरोठिया सदस्य मनोनीत तीन साल तक रहेगा समिति का कार्यकाल

नई दिल्ली । भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने डाक विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करते हुए भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार एवं दोपहर मेट्रो के प्रधान संपादक राजेश सिरोठिया को समिति का सदस्य मनोनीत किया है। समिति का कार्यकाल 29 जुलाई 2026 से तीन वर्ष तक रहेगा ।

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार समिति के अध्यक्ष केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे।गैर-सरकारी सदस्यों में लोकसभा सांसद तापिर गांव, नरेश गणपत म्हास्के, हरिभाई पटेल और शंकर लालवानी, राज्यसभा सांसद डा. मेधा विश्राम कुलकर्णी और डोर्जे त्सोरिंग लेप्चा शामिल हैं। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद से गजेंद्र सिंह

तथा नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी से नंदिनी विश्वकर्मा सदस्य बनाई गई हैं।

संचार मंत्री सिंधिया द्वारा मनोनीत अन्य सदस्यों में हितेंद्र बुधौलिया, वरिष्ठ पत्रकार अनूपम शुक्ला और सुधीर केएस दीक्षित शामिल हैं। वहीं राजभाषा विभाग द्वारा अंकुश गोयल, टोमेंद्र कुमार और उद्धव सिंह को सदस्य मनोनीत किया गया है।

समिति हिंदी के राजकीय कामकाज में प्रयोग, राजभाषा अधिनियम एवं नियमों के क्रियान्वयन तथा केंद्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग के निर्देशों के संबंध में डाक विभाग को सलाह देगी। समिति का मुख्यालय नई दिल्ली रहेगा और इसकी बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली में होंगी।



17 सितंबर से मध्यप्रदेश में सेवा और स्वामित्व का महाअभियान

50 लाख परिवारों को मिलेगी संपत्ति की निःशुल्क रजिस्ट्री, जनसेवा को नया संकल्प देने की तैयारी

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्यप्रदेश में जनसेवा और ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार देने वाले दो बड़े अभियानों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन अभियान और सेवा से संकल्प अभियान को जनभागीदारी के साथ उत्सव के रूप में आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अगले दो दिनों में दोनों अभियानों की माइक्रो प्लानिंग पूरी करने के निर्देश दिए हैं। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन अभियान के तहत प्रदेश के 41 हजार 568 गांवों में सर्वे का काम किया जा चुका है। अब तक करीब 68 लाख 47 हजार प्लॉट का सर्वे पूरा हो चुका है। अभियान के माध्यम से 50 लाख से अधिक हितग्राहियों के नाम पर उनकी संपत्ति की निःशुल्क रजिस्ट्री कराकर उन्हें अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराए जाएंगे।

रजिस्ट्री के लिए पंचायत उपकर और अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। अभियान तीन चरणों में 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र हितग्राही को निष्पक्षता, पारदर्शिता और तय समय-सीमा में योजना का लाभ मिले। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, सचिव, पटवारी और रोजगार सहायक मिलकर प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए शिविर आयोजित करें। प्रत्येक निष्पादन अधिकारी को प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 रजिस्ट्री करने का लक्ष्य दिया गया है।



शाम 7 बजे जलेंगे 58 लाख से अधिक दीप

युवाओं से लेकर आंगनबाड़ियों तक जुड़ेंगे 13 कार्यक्रम

अभियान की शुरुआत आशीर्वाद का दीपक कार्यक्रम से होगी। 17 सितंबर की शाम ठीक 7 बजे प्रदेशभर में लाभार्थी परिवारों के घरों और चर्यानिष्ठ ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों पर 58 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से अपने-अपने जिलों में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थान चिन्हित करने को कहा है। उज्जैन के महाकाल लोक में ही 25 लाख से अधिक दीप जलाने की तैयारी है। इसमें सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ा जाएगा।

सेवा से संकल्प अभियान के तहत 13 प्रमुख गतिविधियां आयोजित होगी। इनमें स्कूलों में सेवा चित्र के तहत चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएं, सेवा स्मरण में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, आंगन का मिलन में बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक कहानियां और बदलाव की कहानियां के माध्यम से हितग्राहियों की सफलता की कहानियों का डिजिटल प्रसार शामिल है। इसके अलावा 7 अक्टूबर को सेवा ज्योति यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु, सेवा के रंग, हैकार्थन एवं इन्वोवेशन चैलेंज जैसे कार्यक्रम होंगे। युवाओं, विद्यार्थियों, स्टार्टअप और कॉर्पोरेट इनोवेटरों को

भी अभियान से जोड़ा जाएगा। जन सेवक महाकुंभ में पंचायत से संसद तक के जनप्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा, जबकि 25 साल 25 कहानियां कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की विकास यात्रा को सामने लाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों अभियान केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनभागीदारी से जनसेवा को नई दिशा देने का बड़ा संकल्प है। उन्होंने कलेक्टरों से अभियान को व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ गांव-गांव तक पहुंचाने और अधिक से अधिक युवाओं तथा आमजन को जोड़ने का आह्वान किया।

शिक्षक संघ एकीकृत का सीएम के नाम ज्ञापन

भोपाल, दोपहर मेट्रो

मध्यप्रदेश में पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता से पूरी तरह मुक्त करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। शिक्षक संघ एकीकृत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयुक्त शिक्षक मोर्चा के संस्थापक सदस्य डॉ. रणजीत मीणा ने प्रदेश सरकार से कर्नाटक की तर्ज पर सेवारत शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से छूट देने की मांग की है। डॉ. मीणा ने भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कर्मचारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष रमेशचंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भोपाल मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से शिक्षक हित में हरसंभव प्रयास किए जाने का

कर्नाटक की तर्ज पर मध्यप्रदेश में सेवारत शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से मिले छूट

न्यायालय के फैसले के बाद सरकार से राहत की उम्मीद

डॉ. मीणा ने सर्वोच्च न्यायालय के अंजुमन इशाअत-ए-तालीम प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि पात्रता परीक्षा के मुद्दे ने लाखों सेवारत शिक्षकों के बीच भविष्य को लेकर चिंता पैदा की है। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा राज्य सरकारों को इस विषय में निर्णय की गुंजाइश दिए जाने के बाद मध्यप्रदेश सरकार को भी कर्नाटक की तर्ज पर पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से छूट प्रदान करनी चाहिए। ज्ञापन में शिक्षक हित से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी उठाए गए। इनमें इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति व्यवस्था में तकनीकी खामियों का समाधान, अतिथि शिक्षकों का

नियमितीकरण एवं 12 माह रोजगार, पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती, शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों के बोझ से मुक्त करना तथा शिक्षा बजट में वृद्धि प्रमुख हैं। डॉ. मीणा ने कहा कि शिक्षक सम्मान, सेवा सुरक्षा और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को इन मांगों पर शीघ्र कारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उनका कहना है कि शिक्षकों को अनावश्यक प्रशासनिक दबाव से मुक्त कर बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।

आश्वासन दिया गया। डॉ. मीणा ने कहा कि मध्यप्रदेश सहित देशभर में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति उस समय निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण

योग्यताओं के आधार पर हुई थी, जब शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य नहीं थी। ऐसे में वर्षों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों पर सेवा के बीच नई पात्रता परीक्षा की

अनिवार्यता लागू करना न्यायसंगत नहीं है।

इसी विषय पर दोपहर मेट्रो का कॉलम प्रशंगवश-पेज 8

छात्रों के लिए बड़ी राहत: सामान्य गणित वाले स्टूडेंट्स भी 11वीं में ले सकेंगे साइंस व मैथ्स

कक्षा 9वीं के नामांकन में विषय परिवर्तन निःशुल्क किया जा सकेगा

भोपाल, दोपहर मेट्रो

प्रदेश के स्कूलों में सामान्य गणित लेकर हाईस्कूल पास विद्यार्थी भी 11वीं कक्षा में विज्ञान विषयों (भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित) की पढ़ाई कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिम) ने नया आदेश जारी कर पुरानी व्यवस्था बदल दी है।

यह होगा फायदा- माशिम के नए आदेश के अनुसार सामान्य गणित विषय से उत्तीर्ण विद्यार्थी भी कक्षा 11वीं में गणित संकाय का चयन कर



सकेंगे। इससे उन विद्यार्थियों को फायदा होगा, जिन्होंने नौवीं में बेसिक गणित चुना है, लेकिन आगे चलकर विज्ञान वर्ग में गणित-विज्ञान विषयों की पढ़ाई करना चाहते हैं।

9वीं में नहीं लगेगा विषय बदलने का शुल्क- माशिम ने

2026-27 सत्र के लिए विषय परिवर्तन की सुविधा भी दी है। सत्र 2025-26 में कक्षा नौवीं के जिन विद्यार्थियों ने विशिष्ट गणित विषय का चयन किया था और अब सामान्य गणित लेना चाहते हैं, वे कक्षा 10वीं के परीक्षा आवेदन-पत्र भरने से पहले अपने कक्षा नौवीं के नामांकन फार्म में निःशुल्क विषय परिवर्तन कर सकेंगे। अभी तक विषय परिवर्तन के लिए 500 रुपये प्रति विषय शुल्क देना होता था। माशिम ने स्पष्ट किया है कि विषय परिवर्तन की यह सुविधा केवल सत्र 2026-27 के लिए लागू रहेगी। कई विद्यार्थी इस नियम के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

मेट्रो एंकर

बच्चों के साथ बैठे जमीन पर, पूछा- नाशता कैसा मिलता है?

भोपाल, दोपहर मेट्रो

महिला एवं बाल विकास विभाग के नवागत आयुक्त संदीप जीआर सीहोर जिले के आंगनवाड़ी केंद्र डोडी क्रमांक-58 पहुंचे। उन्होंने यहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ बच्चों और महिला हितग्राहियों से सीधे बातचीत कर आंगनवाड़ी केंद्र पर मिलने वाली सेवाओं का फीडबैक लिया। बच्चों से उन्होंने नाश्ते और गर्म पके भोजन के स्वाद और गुणवत्ता के बारे में सहजता से जानकारी ली। आयुक्त ने केंद्र पर तीन से छह वर्ष की उम्र के बच्चों को दिए जा रहे नाश्ते और गर्म पके भोजन की गुणवत्ता देखी। एआई के अलावा गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे स्थानीय टेक होम



राशन की स्थिति भी जानी। उन्होंने शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों और अन्य पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का भी अवलोकन किया।

बच्चों के लिए आंगनवाड़ी बने रुचिकर केंद्र- निरीक्षण के दौरान

आयुक्त ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र केवल पोषण वितरण तक सीमित नहीं हैं। यहां बच्चों के समग्र विकास, प्रारंभिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मातृ-शिशु कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं दी जाती हैं। उन्होंने केंद्रों को अधिक सक्रिय,

जीवंत और बाल हितैषी बनाने पर जोर दिया। आयुक्त ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से शाला पूर्व शिक्षा गतिविधियों, पोषण ट्रेकर के इस्तेमाल और कुपोषित बच्चों के उपचार एवं प्रबंधन की जानकारी ली। पोषण ट्रेकर में उपलब्ध वीडियो के

माध्यम से बच्चों के साथ कराई जा रही गतिविधि का उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन भी किया। उन्होंने डिजिटल माध्यमों का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए बच्चों के लिए गतिविधि आधारित और रुचिकर शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पदोन्नति और स्थानांतरण के काम में आएगी तेजी

नई व्यवस्था का सीधा असर स्थापना से जुड़े मामलों पर भी पड़ेगा। पदोन्नति, परीक्षा आदि पूर्ण होने के बाद सेवा की पुष्टि और अन्य कर्मचारी संबंधी प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा आसान होगा। स्थानांतरण, पदस्थापना और संवर्ग प्रबंधन से जुड़े काम भी अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किए जा सकेंगे। हर अधिकारी और कर्मचारी के लिए डिजिटल प्रोफाइल उपलब्ध कराने की योजना है। इसमें सेवा-वृत्त, जीपीएफ की शेष राशि, वेतन पर्ची, अवकाश संबंधी जानकारी सहित सेवा से जुड़ा आवश्यक रिकॉर्ड एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगा। इससे कर्मचारियों को अपनी जानकारी के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।

30 सितंबर तक अपनानी होगी व्यवस्था। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और पोर्टलों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने 30 सितंबर 2026 तक इन पोर्टलों को अपनाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई पूरी करने की अपेक्षा की है। नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों से जुड़े प्रशासनिक कामकाज में कामजी प्रक्रिया घटने और निर्णयों की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है।

एसीआर से लेकर विभागीय जांच तक ऑनलाइन निगरानी। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन यानी एसीआर और एपीएआर से जुड़ी प्रक्रिया को भी डिजिटल माध्यम से अधिक व्यवस्थित किया जाएगा। इससे प्रतिवेदन तैयार करने, आगे भेजने और उसकी निगरानी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं विभागीय जांच के मामलों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। डीई पोर्टल के माध्यम से जांच प्रकरण के पंजीयन से लेकर अंतिम निर्णय तक पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी और स्थिति की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इससे लंबित मामलों पर नजर रखना आसान होगा और प्रकरणों के समयबद्ध निपटारे को बढ़ावा मिलेगा।

सड़क हदसों पर बड़ा एक्शन

30 सितंबर तक भरे जाएंगे सभी गड्ढे, मवेशियों के लिए चलेगा विशेष अभियान

55 जिलों का एक्शन प्लान तैयार, जिलों में सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता

बेसहारा मवेशी, अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर भी होगी सख्ती

भोपाल, दोपहर मेट्रो

सड़क दुर्घटनाओं और इनमें होने वाली जनहानि को कम करने के लिए प्रदेश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता में लिया गया है। सड़क सुरक्षा के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 30 सितंबर तक प्रदेश की सड़कों के सभी गड्ढे भरे जाएं। यह निर्देश मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) के प्रबंध संचालक भरत यादव ने बुधवार को सेव लाइफ फाउंडेशन एवं डीडीएचआई, आईआईटी मद्रास द्वारा प्रदेश में किए जा रहे सड़क सुरक्षा कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए।

उन्होंने कहा कि बेसहारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके जमाव वाले स्थान चिह्नित किए जाएंगे। पशुपालन, नगरीय विकास, जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों के समन्वय से मवेशियों को निकटतम गोशालाओं या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान चलेगा। गोशालाओं की क्षमता और व्यवस्थाओं का आकलन कर जरूरत के अनुसार अस्थायी शेड



डैशबोर्ड और एप से होगी निगरानी

दुर्घटना संभावित स्थानों पर किए जा रहे सुरक्षा कार्यों की निगरानी के लिए मासिक डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इसमें दुर्घटना स्थल, वहां किए जा रहे कार्य और उनकी प्रगति की जानकारी मिल सकेगी। भारतीय सड़क कांग्रेस के मानकों के अनुरूप सेफ स्कूल जोन और मॉडल जंक्शन विकसित करने के प्रस्ताव मुख्यालय भेजे जाएंगे। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के अनिवार्य उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान भी चलाया जाएगा।

बनाए जाएं। लापरवाह पशुपालकों पर कार्रवाई के साथ जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। अवैध पार्किंग और अतिक्रमण को हटया जाए। सड़क निर्माण एजेंसियों को परियोजनाओं की आवश्यक अनुमतिां समय पर लेने के लिए भी कहा गया है, ताकि निर्माण कार्यों में बाधा न आए। इस दौरान बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी द्वारा चर्यानिष्ठ प्रदेश के नौ जिलों फैंटेलिटी जिलों में सड़क सुरक्षा उपाय प्राथमिकता से लागू होंगे।

नक्शे पर खिंची एक रेखा देखने में कितनी छोटी होती है, लेकिन उसके पीछे किसी देश का इतिहास, भूगोल और संप्रभुता खड़ी होती है। इसलिए मानचित्र केवल पहाड़, नदियां, समुद्र और सीमाएं दिखाने वाला कागज नहीं है। वह दुनिया को यह बताने का माध्यम भी है कि कौन-सा भूभाग किस देश से जुड़ा है और उसकी राजनीतिक पहचान क्या है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के नए विश्व मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन की प्रस्तुति को महज तकनीकी भूल मानकर आगे बढ़ जाना उचित नहीं होगा। भारत ने इस विसंगति को संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उठाकर सही किया

है। उसका पक्ष स्पष्ट है कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन भारत के अभिन्न अंग हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा भी एक संवेदनशील वास्तविकता है। इन क्षेत्रों को मानचित्र पर अस्पष्ट ढंग से दिखाना भले ही जमीन पर कोई बदलाव न करे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय धारणा में भ्रम अवश्य पैदा कर सकता है। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। भारत ने विश्व मानचित्रों को अधिक सटीक और न्यायसंगत बनाने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयास का समर्थन किया है। पुराने मानचित्र प्रक्षेपणों में पृथ्वी के कुछ हिस्से

वास्तविक आकार से बड़े दिखाई देते हैं। उन्हें वैज्ञानिक रूप से सुधारना आवश्यक है। लेकिन पृथ्वी के आकार को सही ढंग से दिखाने और किसी देश की सीमा अथवा क्षेत्रीय दावे को अलग ढंग से प्रस्तुत करने के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे पुराने हैं। अक्साई चिन पर भी दोनों देशों की स्थिति अलग है। ऐसे संवेदनशील भूभागों को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था के मानचित्र में यदि अस्पष्टता दिखाई देती है, तो उससे

सवाल उठना स्वाभाविक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार शब्दों से अधिक प्रभाव तस्वीरों का होता है और मानचित्र तो पूरी दुनिया के लिए एक राजनीतिक तस्वीर ही है। यह भी सच है कि नक्शे की कोई रेखा वास्तविक जमीन नहीं बदलती। किसी रंग को बदल देने से किसी भूभाग की संप्रभुता नहीं बदल जाती। लेकिन दुनिया की सामूहिक स्मृति और समझ धीरे-धीरे ऐसे ही प्रतीकों से बनती है। आज की छोटी-सी अस्पष्टता कल किसी बड़ी गलतफहमी का आधार बन सकती है। इसलिए भारत को विरोध दर्ज कराने के साथ लगातार कूटनीतिक संवाद भी बनाए रखना चाहिए।

होर्मुज से उठता तूफान... तेल की घटती आपूर्ति ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को चेताया

कातिलाल मांडेठ
स्तंभकार

परिचय पश्चिम में बढ़ता तनाव अब केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं रह गया है। अमरीका और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। फारस की खाड़ी से तेल निर्यात में सामान्य स्थिति की तुलना में भारी गिरावट इस बात का संकेत है कि युद्ध का आर्थिक प्रभाव कितनी तेजी से दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच रहा है। खाड़ी देशों से तेल निर्यात का करीब 47 प्रतिशत तक रह जाना वैश्विक बाजार के लिए गंभीर चेतावनी है। यदि आपूर्ति में यह कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो तेल की कीमतों में तेजी, परिवहन लागत में वृद्धि और महंगाई का नया दौर देखने को मिल सकता है।

इस पूरे संकट का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होर्मुज जलडमरूमध्य है। यह संकरा समुद्री मार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस के लिए यह मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया के कई बड़े ऊर्जा आयातक देशों की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी समुद्री रास्ते की सुरक्षित आवाजाही पर निर्भर करती है। इसलिए होर्मुज के आसपास किसी भी तरह की सैन्य गतिविधि या जहाजों के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा का असर स्थानीय स्तर से कहीं अधिक व्यापक हो सकता है। ईरान की ओर से होर्मुज के बाहर नए प्रतिबंधित क्षेत्र की बात सामने आने के बाद समुद्री व्यापार को लेकर चिंता बढ़ी है। यदि जहाजों को किसी इलाके में प्रवेश करने से रोकने के लिए सैन्य या प्रशासनिक कदम बढ़ाए जाते हैं तो शिपिंग कंपनियों को वैकल्पिक रास्तों की तलाश करनी पड़ सकती है। इसका सीधा असर यात्रा के समय और लागत पर होगा। तेल टैंकरों के अलावा दूसरे मालवाहक जहाज भी जोखिम वाले क्षेत्र से दूरी बनाने लेंगे तो वैश्विक व्यापार की गति प्रभावित हो सकती है।

तेल की कमी का असर पेट्रोल पंप से लेकर उद्योग तक: तेल केवल वाहनों का ईंधन नहीं है। आधुनिक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ऊर्जा पर निर्भर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन से लेकर कृषि, उद्योग और खुदरा बाजार तक दिखाई देता है। माल ढुलाई महंगी होने पर वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और उत्पादन लागत में भी इजाफा होता है। विमानन क्षेत्र में ईंधन महंगा होने पर हवाई यात्रा की लागत बढ़ सकती है। पेट्रोकेमिकल उद्योग पर असर पड़ने से प्लास्टिक, रसायन और कई औद्योगिक उत्पादों की लागत भी बढ़ सकती है।

यही कारण है कि खाड़ी क्षेत्र से तेल निर्यात में आई बड़ी गिरावट को केवल ऊर्जा बाजार की समस्या मानना उचित नहीं होगा। इसका असर महंगाई पर पड़ सकता है और केंद्रीय बैंकों के लिए आर्थिक नीतियां तय करना कठिन हो सकता है। एक तरफ उन्हें कीमतों को नियंत्रित करने की चुनौती होगी और दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियों को धीमा होने से बचाना होगा। यदि तेल लंबे समय तक महंगा रहता है तो दुनिया के कई देशों की विकास दर पर दबाव पड़ सकता है। भारत दुनिया के प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता देशों में है। देश की अर्थव्यवस्था में परिवहन, विनिर्माण

और सेवा क्षेत्र की बड़ी भूमिका है और इन सभी को ऊर्जा की जरूरत होती है। पश्चिम एशिया में आपूर्ति बाधित होने और अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ने का असर भारत में भी दिखाई दे सकता है। महंगा कच्चा तेल आयात बिल बढ़ा सकता है और इससे विदेशी मुद्रा पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि भारत ने ऊर्जा आपूर्ति को विविध बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं और रणनीतिक तेल भंडार जैसी व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं, लेकिन वैश्विक बाजार में लंबे समय तक आपूर्ति संकट रहने पर उसका असर पूरी तरह टालना मुश्किल होता है। इसलिए भारत के लिए पश्चिम एशिया में शांति और समुद्री मार्गों की सुरक्षा केवल कूटनीतिक विषय नहीं, बल्कि आर्थिक हित का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। होर्मुज के आसपास तेल टैंकरों को निशाना बनाए जाने की खबरों ने स्थिति की गंभीरता बढ़ा दी है। किसी भी समुद्री मार्ग पर व्यापारी जहाजों की सुरक्षा कमजोर पड़ने पर बीमा कंपनियां जोखिम के आधार पर प्रीमियम बढ़ाती हैं। जहाजों के संचालन की लागत बढ़ती है और कई बार कंपनियां लंबे वैकल्पिक रास्तों

का इस्तेमाल करती हैं। इससे एक टैंकर की यात्रा का खर्च बढ़ने के साथ वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लागत भी बढ़ जाती है। यदि ऐसी घटनाएं लगातार होती हैं तो शिपिंग कंपनियों के सामने सुरक्षा और व्यापार के बीच कठिन निर्णय खड़ा हो सकता है। किसी

जहाज का रास्ता बदलने में अतिरिक्त समय और ईंधन लगता है, लेकिन जोखिम वाले इलाके से गुजरना उससे भी बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए समुद्री सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग इस संकट में बेहद जरूरी हो जाता है।

पश्चिम एशिया का संकट इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कई मोर्चों पहले से कनावग्रस्त हैं। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष के साथ गाजा, लेबनान, यमन और इराक से जुड़े तनाव भी क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा रहे हैं। इजरायली मीडिया में ईरान और उसके समर्थित संगठनों की ओर से बड़े बहु-मोर्चीय हमले की आशंकाओं से संबंधित दावे सामने आए हैं। हालांकि ऐसे दावों को अंतिम तथ्य मानने से पहले स्वतंत्र पृष्टि आवश्यक है। यदि वास्तव में एक साथ कई मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई बढ़ती है तो इसका असर केवल संबंधित देशों पर नहीं पड़ेगा। अमरीका और उसके सहयोगियों की सैन्य भूमिका बढ़ सकती है, दूसरे क्षेत्रीय देश भी सीधे या परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं और संघर्ष का दायरा बढ़ने की आशंका पैदा होगी। यही स्थिति पश्चिम एशिया को लंबे समय तक अस्थिर बना सकती है।

इस समय जरूरत सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से अधिक कूटनीतिक प्रयासों की है। अमरीका, ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करनी होगी जिसमें समुद्री मार्ग सुरक्षित रहें और ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो। क्योंकि होर्मुज में पैदा हुआ संकट केवल पश्चिम एशिया का संकट नहीं है। वहां तेल की धार कमजोर पड़ती है तो उसकी लहर दुनिया के बाजारों, उद्योगों और आम उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। पश्चिम एशिया में शांति इसलिए जरूरी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक और बड़े झटके से बचाया जा सके।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

ललित गर्ग
स्तंभकार

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाला 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब विश्व व्यवस्था गहरे संक्रमण से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव, आतंकवाद, व्यापारिक टकराव, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा की चिंता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तेज होती चुनौती और वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्नों ने दुनिया के सामने अनेक अनुत्तरित सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका की व्यापार एवं रणनीतिक नीतियों से पैदा हो रहा दबाव भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ऐसे वातावरण में भारत की अध्यक्षता में होने वाला यह सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत ने अपनी अध्यक्षता का मूल मंत्र रखा है-लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के आधार पर भविष्य का निर्माण। ब्रिक्स अब 2006 में

आरंभ हुई उस मूल अवधारणा से बहुत आगे निकल चुका है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आए थे और बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ। विस्तार के बाद यह 11 सदस्यीय समूह बन चुका है और इसका प्रभाव वैश्विक दक्षिण की राजनीति और अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2026 ब्रिक्स की स्थापना के दो दशक पूरे होने का वर्ष भी है। भारत के लिए यह अध्यक्षता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह ब्रिक्स को किसी पश्चिम-विरोधी या अमेरिका-विरोधी मंच के रूप में नहीं, बल्कि विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की रचनात्मक, संतुलित और बहुपक्षीय आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है।

ब्राजील में 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने, बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार वैश्विक शासन, जलवायु वित्त, स्वास्थ्य, व्यापार और वित्तीय सहयोग जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी। रियो घोषणा में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया था। साथ ही स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय लेन-देन, सीमा-पार भुगतान व्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात कही गई थी। भारत को 2026 की अध्यक्षता सौंपते हुए ब्राजील ने नई दिल्ली से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपेक्षा व्यक्त की थी। इस दृष्टि से दिल्ली सम्मेलन की पहली बड़ी कसौटी यही होगी कि ब्रिक्स घोषणाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच की दूरी कितनी कम कर पाता है। भारत ने अध्यक्षता के दौरान 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग तथा सांस्कृतिक एवं जन-जन संपर्क-इन तीनों क्षेत्रों में व्यवहारिक परिणामों पर जोर दिया गया है। इसलिए अब

दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि सम्मेलन के अंत में केवल लंबा संयुक्त घोषणापत्र सामने आता है या कुछ ऐसे ठोस फैसले भी होते हैं जिनका असर आने वाले वर्षों में दिखाई दे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। एआई ने चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वित्त और शासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं खोली हैं, लेकिन इसके साथ रोजगार, डेटा सुरक्षा, गलत सूचना, साइबर सुरक्षा और तकनीकी असमानता के खतरे भी बढ़े हैं। ब्राजील सम्मेलन में भी एआई के वैश्विक शासन को लेकर व्यापक चिंता व्यक्त की गई थी। भारत अब ब्रिक्स देशों के बीच एआई, उन्नत कंप्यूटिंग, क्वांटम तकनीक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में जोर दे रहा है। यदि ब्रिक्स तकनीक को कुछ शक्तिशाली देशों और कंपनियों के नियंत्रण से बाहर निकालकर विकासशील देशों की पहुंच तक ले आने की प्रभावी व्यवस्था बना सके, तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बड़ी चुनौती आर्थिक है। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का वजन बढ़ रहा है, लेकिन समूह के भीतर आपसी व्यापार अभी भी उसकी संभावित क्षमता के अनुरूप नहीं है। भारत आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत और विविध बनाने, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने तथा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जयपुर में हुई ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स इकनोमिक पार्टनरशिप 2030, एमएसएमई के लिए वित्तीय सुविधा और अधिक संतुलित व्यापार जैसे

मुद्दों पर प्रगति हुई है। लेकिन सम्मेलन की सफलता का वास्तविक पैमाना अमेरिका की आलोचना या पश्चिमी व्यवस्था को चुनौती देना नहीं होगा। सफलता तब मानी जाएगी जब ब्रिक्स दुनिया को बेहतर विकल्प दे-ऐसा विकल्प जिसमें आर्थिक सहयोग हो, तकनीकी साझेदारी हो, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा हो, आतंकवाद के विरुद्ध साझा प्रतिबद्धता हो, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा हो, पर्यावरणीय संतुलन हो और विकासशील देशों की वास्तविक भागीदारी हो। भारत की 'वसुधैव कुटुम्बक' की भावना तभी सार्थक होगी, जब ब्रिक्स शक्ति-संघर्ष का नया अखाड़ा बनने के बजाय सहयोग का नया सेतु बने। अंततः दिल्ली सम्मेलन भारत की कूटनीतिक क्षमता की भी परीक्षा है और ब्रिक्स की प्रासंगिकता की भी। दुनिया आज युद्ध से अधिक शांति, प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग और प्रभुत्व से अधिक साझेदारी चाहती है। मानवता का भविष्य केवल हथियारों, अंतरिक्ष अभियानों या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के बीच विश्वास, सह-अस्तित्व का साझा विकास में सुरक्षित है। यदि नई दिल्ली सम्मेलन घोषणाओं से आगे बढ़कर इस विश्वास को संस्थागत रूप देने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठा सका, तो यह भारत की अध्यक्षता की बड़ी उपलब्धि होगी। अन्यथा ब्रिक्स भी अनेक वैश्विक मंचों की तरह उम्मीदें जगाने वाला, लेकिन अपेक्षाओं पर अधूरा उतरने वाला संगठन बनकर रह जाएगा।

-यह लेखक के अपने विचार हैं।

हेल्थ अपडेट

किशमिश भारतीय रसोई में आसानी से उपलब्ध होते हैं, लेकिन आजकल बहुत से लोग इसे अपनी सुबह की रूटीन में शामिल कर रहे हैं। रात में किशमिश को भिगोकर खाने का नया ट्रेंड चला है। डायटिशियन दीपाली शर्मा, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, सीके बिड़ला हॉस्पिटल, दिल्ली कहती हैं कि किशमिश में निश्चित रूप से बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन पारंपरिक खान-पान के तरीकों और वैज्ञानिक रूप से साबित फायदों के बीच अंतर समझना जरूरी है।

भीगी हुई किशमिश खाने का तरीका सुबह की वेलेनस रूटीन के हिस्से के तौर पर लोकप्रिय हुआ है, खासकर उन लोगों के बीच जो



किशमिश सूखी किशमिश की तुलना में आसानी से पच जाती है और पारंपरिक रूप से इसे पेट साफ रखने और शरीर को पोषण देने वाले खान-पान का हिस्सा माना जाता है। किशमिश से कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल शुगर, डाइटरी फाइबर और

पाचन को बेहतर बनाने और कब्ज से राहत पाने के प्राकृतिक तरीके ढूंढ रहे हैं। किशमिश को भिगोने से वह नरम हो जाती है, जिससे उसे चबाना और सुबह के खाने में शामिल करना आसान हो जाता है। आयुर्वेद के नजरिए से, भीगी हुई

कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इनमें पोटेशियम और थोड़ी मात्रा में आयरन और अन्य मिनरल्स भी होते हैं, साथ ही पॉलीफेनॉलिक कम्पाउंड भी पाए जाते हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। **भीगी किशमिश खाने के फायदे:** किशमिश में कुछ मात्रा में आयरन होता है, लेकिन इसे आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। किशमिश की सामान्य मात्रा से मिलने वाला आयरन अकेले ही आयरन की गंभीर कमी को ठीक नहीं कर सकता। अगर किसी को आयरन की कमी है, तो स्वास्थ्य विशेषज्ञ से इसकी असली वजह का पता लगाना चाहिए और सही इलाज करवाना चाहिए। आयरन के डाइटरी सोर्स, जैसे

दालें, फलियां, पत्तेदार सब्जियां, मीट, अंडे और फोर्टिफाइड फूड, शरीर में आयरन की कुल मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आप कितनी मात्रा में किशमिश खा रहे हैं और साथ में क्या खा रहे हैं। डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों को किशमिश को अपने कार्बोहाइड्रेट इनटेक का हिस्सा मानना चाहिए, न कि यह सोचना चाहिए कि अगर का प्राकृतिक सोर्स होने के कारण इसका ब्लड ग्लूकोज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर, भीगी हुई किशमिश संतुलित आहार में एक पौष्टिक विकल्प हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें यह पसंद है और जो इसे मल त्याग को नियमित रखना चाहते हैं। लेकिन इसे सुबह के 'डिटॉक्स' भोजन के रूप में देखने की जरूरत नहीं है।

निशाना

ब्याज करेगा धोखेबाजी



रामकिशोर नाविक

तू जो ऊलजलूल करेगा अपनी हस्ती धूल करेगा ढेर चढ़ा मालाएँ वो तो श्रद्धाभाव कुबूल करेगा ब्याज करेगा धोखेबाजी काम हमेशा मूल करेगा नकदी रहे मुहब्बतबाजी आके कौन वसूल करेगा पैदा करके लोग सोचते बाकी सब स्कूल करेगा।

टेक्नो अपडेट

आपके बदले ईमेल भेजेगा और ऑनलाइन पेमेंट करेगा Meta का AI एजेंट ‘म्यूज’

मेटा ने अपना पावरफुल AI एजेंट Muse पेश कर दिया है, जो यूजर्स के ईमेल, कैलेंडर, पेमेंट, और स्मार्ट होम जैसे ऐप्स से जुड़कर उनकी तरफ से काम कर सकता है। Muse आपकी तरफ से किसी को ईमेल भेज सकता है, कार बेच सकता है और ट्रेवल बुक कर सकता है। हालांकि, कंपनी को इस बात को लेकर चिंताएं थी कि यह टेक्नोलॉजी पर्सनल डेटा तक पहुंचकर उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले। मेटा का ‘म्यूज’ एजेंट, मार्क जुकरबर्ग की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि मेटा के ऐप्स इस्तेमाल करने वाले अरबों लोगों को एक बेहद स्मार्ट और पावरफुल एआई असिस्टेंट मिले, जो उनके रोजमर्रा के कार्यों में पर्सनल गाइड की तरह मदद कर सके। कंपनी ने अपनी घोषणा में बताया कि यह एआई एजेंट शुरू में सिर्फ अमेरिका यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसे खास ‘म्यूज’ ऐप या मेटा की व्हाट्सऐप मैशेजिंग सर्विस के जरिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। मेटा ने कहा कि वह

इस एजेंट को जल्द ही अपने स्मार्ट ग्लास में भी लाने की योजना बना रहा है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। **अभी फ्री में उपलब्ध:** कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, इस एजेंट का बेसिक वर्जन तो फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल के लिए मेटा 20 डॉलर (लगभग 1,901 रुपये) प्रति महीने और 100 डॉलर (यानी 9,507 रुपये) प्रति महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान पेश करेगा। कंपनी ने कहा कि लोग यह चुन सकते हैं कि एजेंट के साथ हुई उनकी बातचीत का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए ना किया जाए और कंपनी इस साल के आखिर में ‘म्यूज’ का एन्क्रिप्टेड वर्जन भी पेश करने की योजना बना रही है। भारत समेत इसे अन्य देशों में कब लाया जाएगा, फिलहाल इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मेटा ने बताया कि ओपन-सोर्स AI एजेंट ओपनक्लॉ (OpenGlow) पर बेस्ड म्यूज को इस तरह डिजाइन किया गया है यह एआई आपकी ईमेल, कैलेंडर, ऑनलाइन पेमेंट, हेल्थ डेटा, शॉपिंग और स्मार्ट होम जैसी चीजों से जुड़ सकता है। अच्छी बात यह है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा।

जन्माष्टमी पर देशभर में दही हांडी फोड़ने की परंपरा है, लेकिन मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के पास होने वाली दही हांडी अपने अनोखे अंदाज के कारण हर किसी का ध्यान खींचती है। यहां मतकी किसी सड़क या मैदान के ऊपर नहीं, बल्कि करीब 30 फीट गहरे तालाब के बीच हवा में लटकाई जाती है। इसे फोड़ने के लिए गोविंदा तालाब में उतरते हैं और पानी के बीच संतुलन बनाते हुए चुनौती पूरी करने की कोशिश करते हैं। जबलपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर कुआंखेड़ा गांव में होने वाली यह अनोखी दही हांडी वर्षों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सामान्य दही हांडी में गोविंदाओं को एक-दूसरे के कंधों पर चढ़कर ऊंचाई तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन यहां चुनौती अलग है। तालाब की गहराई, पानी और हवा में झूलती मतकी—तीनों मिलकर इसे रोमांचक बना देते हैं। इस आयोजन में मतकी करीब 50 फीट की ऊंचाई पर लटकाई जाती है। उसे फोड़ने की कोशिश में गोविंदा तालाब के पानी में गिरते रहते हैं। इस बार करीब 210 गोविंदा पानी में जा गिरे। देखने वालों के लिए यह नजारा किसी रोमांचक खेल से कम नहीं था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह परंपरा कोई सदियों पुरानी परंपरा नहीं है। गांव के कुछ युवाओं ने करीब 15 साल पहले इसे

शुरू किया था। धीरे-धीरे इसकी चर्चा आसपास के इलाकों तक पहुंची और अब जन्माष्टमी पर यहां बड़ी संख्या में लोग इस अनोखी दही हांडी को देखने पहुंचते हैं। **मतकी तक पहुंचना नहीं:** तालाब में उतरने के बाद गोविंदाओं को सबसे पहले पानी में अपना संतुलन बनाए रखना होता है। इसके बाद लक्ष्य होता है ऊपर हवा में झूल रही मतकी तक पहुंचना। पानी में शरीर का संतुलन जमीनी की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। एक छोटी सी चूक और गोविंदा सीधे गहरे पानी में। यही वजह है कि यहां दही हांडी सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि दम, संतुलन और टीमवर्क की परीक्षा भी बन जाती है। ऊपर से देखने वालों को हर प्रयास के साथ रोमांच बढ़ता जाता है। मतकी टूटते ही तालाब के किनारे खड़े लोगों में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। दही हांडी की सामान्य परंपरा में भी गोविंदा मानव पिपामिड बनकर ऊंचाई पर लटकी मतकी फोड़ते हैं। इसका संबंध भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और माखन-दही की मतकी फोड़ने की कथाओं से जोड़ा जाता है। लेकिन कुआंखेड़ा की दही हांडी ने इस परंपरा को अपनी स्थानीय शैली दे दी है। यहां ऊंचाई के साथ गहरे पानी की चुनौती जुड़ गई है। यही अनोखा अंदाज इसे आसपास के दूसरे आयोजनों से अलग बनाता है।



स्मार्ट मीटर पर भ्रम दूर करने कंपनी ने दिखाई स्मार्ट तस्वीर...

373 शिविरों में 29 हजार 818 उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर निराकरण

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

स्मार्ट मीटर को लेकर आम जनता (उपभोक्ताओं) के बीच चल रही शंकाओं और भ्रांतियों को दूर करने के लिए मप्र विद्युत वितरण कंपनी ने गुरुवार को इटारसी में मीडिया के सामने इसकी पूरी कार्यप्रणाली रखी। अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट मीटर पुराने मीटर की तरह ही बिजली की खपत मापता है, लेकिन नई तकनीक के कारण रीडिंग, बिलिंग और खपत की जानकारी उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा आसान और पारदर्शी हो जाती है। मीडिया वर्कशॉप में प्रेजेंटेशन और तीन शॉर्ट फिल्मों के जरिए स्मार्ट मीटर के फायदे और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। तय समय अनुसार 45मिनट



की वर्कशॉप डेढ़ घंटे तक चली। पुराने मीटर जैसा ही, तकनीक हुई स्मार्ट... मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के उप मुख्य महाप्रबंधक (स्मार्ट मीटरिंग सेल) सी.के. पवार ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि स्मार्ट मीटर भी पुराने मीटर की तरह बिजली की खपत मापता है, लेकिन इसमें आधुनिक तकनीक और सिम की सुविधा जोड़ी गई है। उन्होंने

बताया कि विद्युत स्मार्ट मीटर लगने के बाद परिसर में रीडिंग लेने आने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक सटीक रीडिंग होती है।उपभोक्ता मोबाइल के जरिए बिजली खपत से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। हर माह एक तारीख को मीटर रीडिंग और बिल जनरेट होने से बिलिंग में देरी की समस्या खत्म हो गई है। पुराने मीटर में रीडिंग और बिल बनने के बीच 15 से 20 दिन तक का

अंतर रहता था। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत और लोड मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच बिजली का उपयोग करने पर उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत छूट का प्रावधान भी बताया गया। पोस्टपेड व्यवस्था के साथ प्रीपेड सुविधा पर भी काम किया जा रहा है। उपभोक्ता अपनी इच्छा से प्रीपेड

मीटर का विकल्प चुन सकते हैं।पवार ने यह भी बताया कि स्मार्ट मीटर को लेकर यह भ्राति है कि इन्हें लगाने का काम बंद कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने की समय-सीमा बढ़ाई है। मीटर लगाने से पहले तीन स्तर पर परीक्षण किया जाता है। कंपनी ने बिल के फॉर्मेट में भी सुधार किया गया है।एसडीएम निलेश शर्मा ने कहा कि बिजली कंपनी से जुड़े सभी लोग कंपनी के उपभोक्ता हैं, इसलिए स्मार्ट मीटर का मुद्दा हर व्यक्ति से जुड़ा है। मीडिया वर्कशॉप से उपभोक्ताओं के बीच स्मार्ट मीटर को लेकर बनी भ्रांतियां दूर होंगी और जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर में अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं।

मौके पर ही समस्याओं का समाधान... महाप्रबंधक मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी नर्मदापुरम विनीत कुमार बागड़े ने बताया कि कंपनी का संपर्क अभियान 2026 काफी सफलता रहा है। संपर्क अभियान का उद्देश्य यह है कि उपभोक्ता समस्या लेकर कंपनी के कार्यालय तक पहुंचें, उससे पहले ही कंपनी की टीम उनके घर, गांव और वाई तक पहुंचे। वितरण केंद्र स्तर पर शिविर लगाकर मौके पर ही समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नाम परिवर्तन, लोड कम करना, एनओसी प्रमाण-पत्र, बंद या खराब मीटर जैसी शिकायतों का मौके पर निराकरण किया गया। नर्मदापुरम जिले में अब तक 373 संपर्क शिविर लगाए जा चुके हैं।

न्यूज विंडो

उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टर की पत्नी की मध्य प्रदेश के छतरपुर में सदिग्ध मौत



छतरपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात अनोज कुमार राजपूत की 28 वर्षीय पत्नी संगीता देवी राजपूत की छतरपुर के मिशन अस्पताल में इलाज के दौरान सदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही मायके पक्ष के लोग अस्पताल पहुंच गए और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना तथा जहरीला पदार्थ खिलाकर जान से मारने का आरोप लगाते हुए देर रात जमकर हंगामा किया। मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तीन दिन में अपहृता दस्तयाब, पुलिस ने परिजनों को किया सुपुर्द



तेंदूखेड़ा। थाना तेंदूखेड़ा पुलिस ने अपहृता से जुड़े प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन दिन के भीतर उसे दस्तयाब कर लिया। थाना तेंदूखेड़ा में अपराध क्रमांक 353/2026, धारा 137(2) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने अपहृता की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर जानकारी जुटाते हुए लगातार प्रयास किए। पुलिस की सक्रियता और तत्परता के चलते अपहृता को तीन दिन के अंदर दस्तयाब करने में सफलता मिली। दस्तयाबी के बाद पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई तथा अपहृता को सुरक्षित रूप से उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसके साथ ही पुलिस ने अपहृता को मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना किया। प्रकरण में पुलिस द्वारा आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से शुरू होगा भाजपा का सेवा संकल्प अभियान



तेंदूखेड़ा। भारतीय जनता पार्टी मंडल तेंदूखेड़ा में बुधवार को कार्यसमिति की मासिक बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी मनीष तिवारी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। जिसमें प्रधानमंत्री के लिए प्रत्येक बृथ पर प्रत्येक परिवार के द्वारा आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। सभी मंडल के के कार्यकर्ता एक जगह एकत्रित होकर तालाब, बावड़ी, सार्वजनिक स्थल पर दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। लगभग 1 माह विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसकी जानकारी कार्यकर्ताओं एवं मंडल के पदाधिकारियों को दी गई। बैठक में मंडल अध्यक्ष जिला महामंत्री रामेश्वर चैधरी, सांसद प्रतिनिधी मूरत सिंह लोधी, नगर परिषद अध्यक्ष सुरेश जैन, विधानसभा प्रभारी गोविंद यादव शुभम जैन आदि मौजूद थे।

मेट्रो एंकर

इटारसी में रेलकर्मियों की टीम ने बनाई 251 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं

इयूटी के बाद मिट्टी को दे रहे गणेश का आकार, 18 साल से जारी है अनूठी पहल

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच समय निकालना आसान नहीं, लेकिन कुछ रेलकर्मियों ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। इटारसी में रेलकर्मियों की एक टीम पिछले 18 साल से गणेश चतुर्थी के पहले मिट्टी की प्रतिमाएं तैयार कर रही है। इस बार टीम ने 251 इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं को आकार दिया है। खास बात यह है कि इन प्रतिमाओं की बिक्री नहीं होगी, बल्कि गणेश चतुर्थी पर इन्हें लोगों को नि:शुल्क



वितरित किया जाएगा। इटारसी स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक विनोद चौधरी ने वर्ष 2008 में 101 मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बनाकर इस पहल की शुरुआत की थी। समय के साथ परिवार और रेलवे

के अन्य कर्मचारी भी इस अभियान से जुड़ते गए। अब यह अभियान 18वें वर्ष में पहुंच चुका है। पिछले करीब 8-10 दिनों से चौधरी अपनी टीम के साथ प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

हर प्रतिमा के साथ पर्यावरण का संदेश

हर साल प्रतिमाओं के लिए अलग-अलग थीम चुनी जाती है। इस बार करीब पांच-छह थीम पर प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। इनमें ब्रिक्स-2026, स्वच्छ भारत अभियान, पेड़ बचाओ, पानी बचाओ और पृथ्वी बचाओ जैसी थीम शामिल हैं। प्रतिमाओं के जरिए गणेश उत्सव के साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। प्रतिमाओं को मिट्टी, रंगोली और कच्चे रंगों से तैयार किया जा रहा है। चौधरी और उनकी टीम 3 सितंबर से रोजाना सुबह करीब 8 बजे से रात 10 बजे तक प्रतिमाओं को आकार देने और अंतिम रूप देने में जुटी है। मिट्टी की प्रतिमाएं विसर्जन के बाद पानी में आसानी से घुल जाती हैं, जिससे प्रदूषण का खतरा कम होता है। इस अभियान में विनोद चौधरी के परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी पत्नी अर्चना, बेटी अनुष्का और बेटा आयुष प्रतिमाएं तैयार करने में सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे के डिप्टी एसएस गोपाल कुशवाहा, दिलीप कुमार, ओएस अमित चौधरी, स्टेशन असिस्टेंट राजकुमार और रेलवे गार्ड की पत्नी रचना तिवारी, रितु डेहरिया सहित अन्य रेलकर्म भी प्रतिमाओं को आकार देने में हाथ बंटा रहे हैं।

गौशाला परिसर में कथा सुनाते गौ पीठाधीश्वर पं. विपिन बिहारी दास महाराज

भगवान का नाम जीवन को सुंदर बनाता

है, कर्मों का कोई उत्तराधिकारी नहीं

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

नगर में आचार्य श्री विद्यासागर दयोंदय पशु सेवा केंद्र गौशाला परिसर में 9 से 15 सितंबर तक आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंचे। कथा व्यास श्री गौ पीठाधीश्वर पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज ने श्रद्धालुओं को भगवान के नाम, सद्कर्म, माता-पिता के प्रति प्रेम और जीवन में धर्म के महत्व का संदेश दिया।

महाराज ने कहा कि मानव जीवन में हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, क्योंकि संसार में भगवान ही सच्चे हैं। व्यक्ति की संपत्ति के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उसके कर्मों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। इसलिए कर्म करते समय सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई देखे या न देखे, ऊपर वाला सब देख रहा है। उन्होंने गुरु और शिष्य की कथा सुनाते हुए बताया कि गुरु ने दो शिष्यों को ऐसी जगह केला खाने के लिए कहा, जहां उन्हें कोई न देख रहा हो। एक शिष्य ने इधर-उधर देखकर केला खा लिया, जबकि दूसरे ने कहा कि ऐसी कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि भगवान उसे हर जगह देख रहे थे। महाराज ने कहा कि सही अर्थों में



वही दीक्षा का अधिकारी था, जिसने ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझा। उन्होंने कहा कि दुनिया में माता-पिता से निस्वार्थ प्रेम करने वाला कोई नहीं होता। जीवन में समय बहुत बलवान है, इसलिए अच्छे समय में अच्छे कार्य कर लेने चाहिए। भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए और मृत्यु को भी हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने जन्मदिन मनाने की भारतीय परंपरा अपनाने का संदेश देते हुए कहा कि जन्मदिन पर भगवान के दरबार में घी के दीपक जलाएं और गौ माता को लड्डू खिलाएं। महाराज ने कहा कि हाथ में माला हो या न हो, लेकिन जरूरतमंद की मदद करने

वाले हाथ जरूर होने चाहिए। माथे पर चंदन लगाएं या न लगाएं, लेकिन किसी के जख्म पर मरहम लगाना सीखें। उन्होंने भागवत के नियमों, राजा परीक्षित को मिले श्राप और महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रसंग सुनाते हुए धर्म और अधर्म का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि संख्या से नहीं, धर्म और सत्य के साथ खड़े होने से विजय मिलती है। परिवार में प्रेम बनाए रखें, चरणों की नहीं बल्कि आचरण की पूजा करें। संतों के दर्शन करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। अंत में उन्होंने कहा कि जीवन में पिता और गुरु का स्थान सर्वोच्च है। शिक्षा सभी से लें, लेकिन गुरु एक ही रखें।

दोबारा सड़क खराब हुई तो एजेंसी पर होगी कार्रवाई

सीवर लाइन की धीमी रफ्तार पर कलेक्टर नाराज

बोले- रेस्टोरेशन में गुणवत्ता से समझौता नहीं

नर्मदापुरम। दोपहर मेट्रो

शहर में धीमी गति से चल रहे सीवर लाइन के काम पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने नाराजगी जताई है। गुरुवार को सीवर लाइन कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होंने एमपीयूडीसी के अधिकारियों को काम में तेजी लाने और तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि सीवर लाइन डालने के बाद सड़कों की हालत खराब छोड़ना स्वीकार नहीं किया जाएगा। बारिश खत्म होने के बाद सड़क रेस्टोरेशन शुरू किया जाए और इसमें सड़क की मजबूती व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

कलेक्टर ने कहा कि जिन स्थानों पर सीवर लाइन का काम पूरा हो चुका है, वहां सड़क रेस्टोरेशन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। रेस्टोरेशन की गुणवत्ता खराब होने और अनयूजुअल रेस्टोरेशन पर उन्होंने



अधिकारियों से सुधार करने को कहा। सीवर लाइन के कारण सड़कों की स्थिति लगातार प्रभावित होने पर नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए काम और रेस्टोरेशन दोनों की निगरानी जरूरी है। कलेक्टर ने शहर के सभी वार्डों को वार्डवार और जोनवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसमें सीवर लाइन के पूर्ण कार्य को ग्रीन, प्रगतिरत को ऑरेंज और अपूर्ण कार्य को लाल रंग से चिह्नित किया जाएगा। अधिकारियों को इसकी अद्यतन

जानकारी पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रत्येक वर्ड में सीवर लाइन के काम की स्थिति स्पष्ट हो सके। सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद सड़क रेस्टोरेशन से जुड़ी सीएम हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से मिलने वाली शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि काम के दौरान नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो और सीवर लाइन व सड़क रेस्टोरेशन की लगातार निगरानी की जाए।

जैन धर्मशाला चोरी मामले में आरोपी धराया, 25 चांदी के कलश बरामद



तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

जैन धर्मशाला तेन्दूखेड़ा से चांदी के कलश चोरी होने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी गए 25 चांदी के कलश बरामद किए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 नवंबर 2025 को वाई क्रमांक 08 निवासी भागचंद पिता स्व. गुलाबचंद जैन, उम्र 58 वर्ष, ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जैन धर्मशाला से अज्ञात चोर 50 नग चांदी के कलश चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना में मामला दर्ज कर आरोपी एवं चोरी गए

मशरूके की तलाश शुरू की गई। जांच के दौरान थाना कोतवाली दमोह के अपराध क्रमांक 753/2026 में गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार जैन पिता मुलायमचंद्र जैन, उम्र 58 वर्ष, निवासी विश्वनाथ कॉलोनी छतरपुर के इस मामले में सदिग्ध होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी से पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने तेन्दूखेड़ा जैन धर्मशाला में चोरी करना स्वीकार किया। न्यायालय से पुलिस रिमांड प्राप्त कर आरोपी की निशानदेही पर जैन धर्मशाला से चोरी किए गए 25 चांदी के कलश जब्त किए गए।

तहसील कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर झूली पेड़ों की डालियां

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

नगर के तहसील कार्यालय के सामने मुख्य सड़क मार्ग पर सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों की डालियां सड़क के उपर होने से बड़े वाहनों से आए दिन बड़ी बड़ी डालियां टकराती हैं, किसी दिन कोई बड़ी डाली टूटकर गिरने से गंभीर दुर्घटना घटित हो सकती हैं। तहसील कार्यालय के सामने सड़क के दोनों तरफ छोटे छोटें दुकानदार अपनी दुकान लगाए रहते हैं इसके अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी रहते हैं। साथ ही लोगों के वाहन भी सड़क के बाजू से खड़े रहते हैं। जैसे ही कोई बड़ा वाहन निकलता है पेड़ों की बड़ी डालियां उपर की छत



से टकराती हैं इसके अलवा दो वाहनों की क्रासिंग के समय तो और खतरनाक हो जाता है दोनों वाहन की छत दोनों तरफ के पेड़ों की डालियों से टकराते हैं। तहसील कार्यालय के सामने के दुकानदारों का कहना है कि जल्द से जल्द पेड़ों की छटाई करवाई जाए नहीं तो किसी दिन बड़ी दुर्घटना घटित हो जाएंगी।

न्यूज विंडो

इंदौर : अपोलो टावर में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाह, प्रशासन ने सील किया



इंदौर। इंदौर शहर के सबसे पुराने बहुमंजिला मार्केट अपोलो टावर में फायर सेफ्टी को लेकर घोर लापरवाही सामने आने के बाद नगर निगम ने बुधवार दोपहर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूरे टावर को सील कर दिया। टावर में 600 से ज्यादा दुकानें संचालित हैं और रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर कोई इंतजाम नहीं थे।

भिंड : गोला का मंदिर मार्ग पर तेज रफ्तार बेकाबू कार देर रात एक घर में जाकर घुसी



ग्वालियर। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में भिंड रोड पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। यहां करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से दौड़ रही एक बेकाबू कार सीधे एक मकान में जा घुसी। इस भीषण हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार चला रहे ड्राइवर समेत सभी चारों लोग नशे में धुत थे।हादसा रात करीब ढाई बजे का है। हादसे के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और सभी घायलों को इलाज के लिए निजी रिस्म (ऋद्धिक्स्) अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटनाग्रस्त कार पर दिल्ली का नंबर दर्ज है, लेकिन उसमें सवार चारों युवक स्थानीय दीनदयाल नगर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

टीकमगढ़ : जतारा इलाके की लार नदी में गिरी कार, चालक सुरक्षित बचा



टीकमगढ़। जिले के जतारा इलाके में लार नदी के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। यहां एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 20 फीट नीचे नदी में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार चालक सुरक्षित बच गया। कार के नदी में गिरने की सूचना मिलते ही जतारा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए मशक्कत के बाद कार को नदी से बाहर निकलवाया।

सड़कों पर घूम रही बेसहारा गौ माता को नगरपालिका ने भेजा गौशाला



गंजबासौदा। शहर की सड़कों पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों के कारण दुर्घटनाओं की बढ़ती आशंका को देखते हुए नगर पालिका ने गुरुवार को कार्रवाई की। नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव के निर्देश पर अमले ने काऊ कैचर की मदद से विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर दो दर्जन से अधिक मवेशियों को पकड़ा और उन्हें गौशाला भिजवाया। नगर के जयस्तंभ चौक, स्टेशन रोड, बरेठ रोड, गल्ला मंडी, एसडीएम कार्यालय के सामने और पुरानी अनाज मंडी सहित प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में मवेशी सड़क पर बैठे या घूमते नजर आते हैं। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी के साथ दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है। रात के समय सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को दिखाई नहीं देने से स्थिति और गंभीर हो जाती है। बेसहारा मवेशियों को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अमले को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद काऊ कैचर वाहन के साथ टीम ने शहर के प्रमुख मार्गों पर अभियान चलाया गया।

मेट्रो एंकर

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बाघिन के इलाज के बाद पुनर्वास की तैयारी प्राकृतिक वातावरण में अभ्यस्त होने पर लौटेंगी अपने घर

जंगल लौटने से पहले बाघिन भोपाल वन विहार में सीखेगी जीने के हुनर

तेंदूखेड़ा। दोपहर मेट्रो

दो महीने से इलाज और निगरानी में हू अब जंगल की खुली हवा में लौटने का इंतजार है, लेकिन नौरादेही अभ्यारण्य पहुंचने से पहले मुझे वन विहार में कुछ दिन रहना होगा। शिकार करना और अपने दम पर भोजन तलाशना सीखूंगी जब नए ठिकाने में पुरी तरह रम जाऊंगी तभी अपने पुराने घर लौट पाऊंगी..... यह बाघिन की कही हुई बात नहीं बल्कि उसके पुनर्वास की अगली कहानी है। दरअसल दो माह पहले 8 जुलाई को कमजोर हालत में मिली 20 माह की बाघिन को इलाज के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू कर



जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वन्यजीव चिकित्सा केंद्र भेजी गई थी। बाघिन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और अब उसका नया ठिकाना भोपाल वन विहार तय हुआ है वन विभाग ने उसे सीधे नौरादेही

अभ्यारण्य के जंगल में छोड़ने के बजाय पहले उसे वन विहार भेजने का फैसला किया है। विभाग ने विश्वविद्यालय प्रशासन को इसकी जानकारी भी दे दी है। अब जल्द ही बाघिन को जबलपुर से भोपाल वन विहार भेजने की तैयारी की जाएगी।

पहले चोटिल हुई फिर केनाइन डिस्टेंपर से जूझी बाघिन

बाघिन को वन विहार भेजने की तैयारी टीम कर रही है और उम्मीद है कि 2-3 दिन में उसे भोपाल ले जाया जाएगा। इस युवा बाघिन ने कम उम्र में ही कई बाधाओं को पार किया है। बताया जाता है कि नौरादेही टाइगर रिजर्व के मोहली परिक्षेत्र में बाघिन ने 5 जुलाई को एक श्रमिक पर हमला किया था। इसके बाद वन्य कर्मियों को गश्त के दौरान वह भूखी और चोटिल नजर आई थी, लेकिन उसे पकड़ा जाता इसके पहले ही वह गायब हो गई। इसके बाद 8 जुलाई

को घायल बाघिन को पकड़कर वेंटरनरी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेंसिक हेल्थ सेंटर भेजा गया जहां जबलपुर में शुरुआती जांच में उसकी केनाइन डिस्टेंपर रिपोर्ट निगेटिव थी, लेकिन बाद में हुई जांच में वह पॉजिटिव पाई गई और बहुत कमजोर हो गई थी जबलपुर के वेंटरनरी चिकित्सकों की अथक मेहनत और हर संभव उपचार से बाघिन अब पूरी तरह ठीक हो गई है वन विहार में बाघिन के व्यवहार और जंगल में रहने की क्षमता का आकलन करने के बाद ही उसे नौरादेही में छोड़ने का फैसला होगा। परिवहन, स्वास्थ्य परीक्षण

और दूसरी जरूरी तैयारियां पूरी होने के बाद उसे वन विहार ले जाया जाएगा जबलपुर वेंटरनरी के चिकित्सकों ने बताया कि शुरुआत में बाघिन जब घायल थी, तब वह कुछ ज्यादा नहीं खा पाती थी, लेकिन बाद में जब वह ठीक हुई तो 4 से 5 किलो मीट खा रही थी। उस पर नजर बनाए रखी और यही परिणाम है कि अब वह पूरी तरह ठीक होकर वन विहार भोपाल जाने वाली है अस्पताल से बाहर निकलना उसके लिए जंगल वापसी का पहला कदम होगा। बाघिन पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। उसे वन विहार भेजने का निर्णय लिया गया है।

सागर के नवपदस्थ आईजी इरशाद वली ने बंडा का जायजा लिया



सागर। बंडा क्षेत्र में हुए जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सागर संभाग के नवपदस्थ आईजी इरशाद वली ने पदभार ग्रहण करने के बाद सीधे बंडा पहुंचकर मामले से जुड़े संभावित ठिकानों का जायजा लिया। आईजी कथित तौर पर शराब कांड के मुख्य केंद्र रहे तत्तुवारा गांव पहुंचे और यहां खेतों में अवैध शराब बनाए जाने की सामने आई जानकारी के संबंध में पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।

ब्लेंडर्स प्राइड, रॉयल स्टैग सहित 12 ब्रांड की शराब बरामद, आबकारी एक्ट में केस दर्ज

हीरापुर में मकान का शराब गोदाम के रूप में किया जा रहा था उपयोग, 261 लीटर विदेशी शराब जब्त

सागर। दोपहर मेट्रो

जिले में जहरीली एवं अवैध मदिरा के विनिर्माण, विक्रय, संग्रहण एवं परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग एवं सागर पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर प्रतिभा पाल एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशानुसार आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बंडा, ग्राम हीरापुर, चौकी हीरापुर, थाना शाहगढ़ क्षेत्र में एक मकान का उपयोग अवैध शराब के गोदाम के रूप में किया जा रहा है।

मुखबिर द्वारा यह भी सूचना दी गई कि उक्त मकान में रखी गई अवैध शराब का संबंध बंडा जहरीली शराब प्रकरण के आरोपी मनीष लोधी से है। प्राप्त सूचना की तस्दीक एवं अवैध शराब के स्रोत का पता लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा पुलिस बल, चौकी हीरापुर के साथ मौके पर पहुंचकर संबंधित मकान की विधिवत तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान मकान से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी/विदेशी मदिरा बरामद हुई। बरामद शराब में ओल्ड मोक व्हिस्की, लंदन प्राइड वोदका, ब्लेंडर्स प्राइड व्हिस्की, गोवा रम, व्हाइट मिश्चिफ, रॉयल सिलेक्ट, फॉक्स



ऑरेंज, 8 पीएम व्हिस्की, महावत व्हिस्की, रॉयल स्टैग व्हिस्की, ग्रीन लेबल व्हिस्की एवं ब्लैक फोट रम सहित विभिन्न ब्रांड की विदेशी मदिरा शामिल है।

मौके से कुल 261 बल्क लीटर अवैध विदेशी मदिरा बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹2,80,000 है। उक्त कार्रवाई के संबंध में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) एवं 34(2) के तहत

प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आबकारी विभाग एवं पुलिस द्वारा मुखबिर से प्राप्त उस सूचना की भी तस्दीक की जा रही है, जिसमें बरामद अवैध शराब का संबंध बंडा जहरीली शराब प्रकरण के आरोपी मनीष लोधी से बताया गया है। साथ ही बरामद शराब के वास्तविक स्रोत, आपूर्ति श्रृंखला एवं इसमें संलिप्त अन्य व्यक्तियों के संबंध में भी जांच की जा रही है।

धार नगर पालिका की परिषद बैठक में गूंजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एफआईआर का मामला

अटके प्रोजेक्ट पर पार्षदों ने अधिकारियों को घेरा, संपत्तिकर में मिलेगी 10 प्रतिशत की छुट

धार। दोपहर मेट्रो

नगर पालिका परिषद की बैठक गुरुवार को आयोजित हुई। बैठक में भाजपा से नवनियुक्त पांच एलडरमैन ने पहली बार भाग लिया। अध्यक्ष नेहा महेश बोड़ाने, सीएमओ कुंवर विश्वनाथ सिंह, पार्षदों और नगर पालिका कर्मचारियों की मौजूदगी में शहर के विकास से जुड़े 25 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से एक को छोड़कर 24 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।बैठक की शुरुआत में कांग्रेस पार्षदों ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर हंगामा किया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि परिषद की सहमति के बिना कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि दूषित



पेयजल आपूर्ति के विरोध में प्रदर्शन करने पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। कांग्रेस पार्षदों ने एफआईआर निरस्त करने की मांग की। इस पर सीएमओ ने लीगल एडवाइज लेकर मामले का निराकरण करने की बात कही।

बैठक में भाजपा और कांग्रेस दोनों पक्षों के पार्षदों ने शहर में धीमी गति से चल रहे विकास कार्यों को

लेकर नगर पालिका अधिकारियों को घेरा। पार्षदों ने कहा कि बस स्टैंड निर्माण को तीन साल से अधिक समय हो चुका है, जबकि हटवाड़ा कॉम्प्लेक्स का काम अब तक शुरू नहीं हुआ। पार्षद करीम कुशैरी ने कहा कि ठेकेदार समय पर काम पूरा नहीं करते और कार्रवाई होने पर न्यायालय से स्टे ले आते हैं। ऐसे में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

रीवा के संजय गांधी अस्पताल का मामला

सुरक्षा को लेकर देर रात डॉक्टर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे



रीवा। दोपहर मेट्रो

संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। देर रात करीब 50 रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। डॉक्टरों का आरोप है कि दूध वार्ड में पांच युवक शराब के नशे में घुस आए और एक डॉक्टर के साथ मारपीट की। घटना के बाद डॉक्टरों में काफी आक्रोश है। घटना से नाराज करीब 50 रेजिडेंट डॉक्टर बुधवार रात लगभग 12 बजे अस्पताल के बाहर जमीन पर बैठ गए।

डॉक्टरों ने सुरक्षा की टोस व्यवस्था की मांग करते हुए काम का बहिष्कार करने का ऐलान किया। रेजिडेंट डॉक्टरों के मुताबिक, रात में पांच युवक शराब के नशे में दूध वार्ड के अंदर पहुंच गए। इस दौरान एक डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। घटना के बाद अस्पताल में हंगामे जैसी स्थिति बन गई। डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। डॉक्टर अस्पताल में सुरक्षा की स्थायी और प्रभावी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं।

प्यारी नंबर-2 में पंचायत निर्माण कार्य पर सवाल बाउंड्रीवॉल, चेकडैम-पुलिया तक की मिली शिकायतें

कोतमा/अनूपपुर। दोपहर मेट्रो

ग्राम पंचायत प्यारी नंबर-2 और सोही वेलहा में कराए गए विभिन्न निर्माण कार्यों को लेकर सामने आए शिकायत एवं विभागीय दस्तावेजों ने निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी जांच और शासकीय राशि के उपयोग को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। मामला केवल एक निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्रीवॉल, चेकडैम/स्टॉपडैम, पुलिया तथा अन्य पंचायत निर्माण कार्यों से जुड़ी शिकायतों में गुणवत्ता और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार सीएम हेल्पलाइन शिकायत क्रमांक 24221992, दिनांक 15 सितंबर 2023 में मर्रेणा अंतर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में

बाउंड्रीवॉल निर्माण सहित संबंधित कार्यों की जांच की मांग की गई। विभागीय निराकरण रिपोर्ट में संबंधित निर्माण का निरीक्षण किए जाने तथा तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलन के अनुसार कार्य होने का उल्लेख है। रिपोर्ट में निर्माण की गुणवत्ता संतोषजनक पाए जाने और पूर्व में भी जांच किए जाने की बात दर्ज है। शिकायत को बाद में निराकृत/बंद किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि उपलब्ध दस्तावेजों में शिकायतकर्ता की ओर से निर्माण की वास्तविक गुणवत्ता, पीसीसी की मोटाई, माप और निर्माण सामग्री को लेकर आपत्तियां दोबारा दर्ज दिखाई देती हैं। यही स्थिति जांच प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े करती है कि क्या गुणवत्ता का परीक्षण केवल मद के निरीक्षण तक सीमित रहा या निर्माण सामग्री एवं कार्य की स्वतंत्र तकनीकी

जांच भी कराई गई? शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्यारी नंबर-2 की उपलब्ध तकनीकी ड्राइंग में बाउंड्रीवॉल की लंबाई 212 मीटर दर्शाई गई है। ड्राइंग में विभिन्न हिस्सों के माप भी अंकित हैं। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि स्वीकृत ड्राइंग और प्राक्कलन में जितना कार्य प्रस्तावित था, मौके पर उतना ही कार्य हुआ या नहीं। इसके लिए मौके पर दोबारा माप लेकर उसे माप पुस्तिका (स्क्च), तकनीकी प्राक्कलन और भुगतान रिकॉर्ड से मिलाने की आवश्यकता है। शिकायतों में ग्राम पंचायत सोही वेलहा एवं प्यारी नंबर-2 में चेकडैम/स्टॉपडैम और पुलिया निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि कुछ निर्माण ऐसे स्थानों पर किए गए जिनसे ग्रामीण किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।

सागर के नवपदस्थ आईजी इरशाद वली ने बंडा का जायजा लिया



सागर। बंडा क्षेत्र में हुए जहरीली शराब कांड के बाद पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सागर संभाग के नवपदस्थ आईजी इरशाद वली ने पदभार ग्रहण करने के बाद सीधे बंडा पहुंचकर मामले से जुड़े संभावित ठिकानों का जायजा लिया। आईजी कथित तौर पर शराब कांड के मुख्य केंद्र रहे तत्तुवारा गांव पहुंचे और यहां खेतों में अवैध शराब बनाए जाने की सामने आई जानकारी के संबंध में पुलिस अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।

शिक्षकों के लिए अनिवार्य इस ‘टेट ’ का आखिर औचित्य क्या है?

सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह है और अब यह साफ है कि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए भी टीईटी (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) की अनिवार्यता को अदालत ने बरकरार रखा है। 29 मई 2026 के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इन-सर्विस शिक्षकों को टीईटी हासिल करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ाई थी। अदालत ने राज्यों से यह भी कहा है कि टीईटी नियमित रूप से, संभव हो तो साल में दो बार आयोजित किया जाए, ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके । लेकिन अदालत के फैसले के बाद भी एक सवाल अपनी जगह कायम है की वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक की पेशेवर क्षमता को परखने का सबसे उपयुक्त तरीका आखिर क्या है? मध्य प्रदेश में इस सवाल पर इसलिए भी विचार होना चाहिए क्योंकि राज्य शिक्षा केंद्र और उससे जुड़ी शैक्षणिक संस्थाएं पहले से ही कार्यरत शिक्षकों के लिए लगातार प्रशिक्षण और क्षमता-विकास कार्यक्रम चलाती रही हैं। नई शिक्षा प्रणाली, नए पाठ्यक्रम, शिक्षण की नई तकनीक, डिजिटल शिक्षा और बदलती शैक्षणिक जरूरतों से शिक्षकों को परिचित कराने के लिए नौकरी

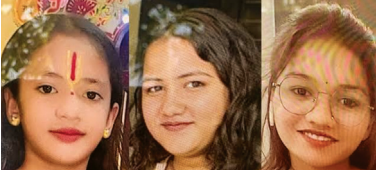
न्यूज विडो

कानपुर: दवा कारोबारी की हत्या में आया नया मोड़



कानपुर. एजेंसी। दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हई हत्या में अब नई सामने आई है। इससे पुलिस की जांच की दिशा बदल गई है। हत्या की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद शालू के भाई-बहन ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। भाई ने बहन को बेकसूर बता दावा किया कि शालू ने हत्या की साजिश नहीं रची। इतेफाक से उस रात किटी पार्टी की आयोजक शालू थी, लेकिन ये आरोप पालत हैं कि ससुर की हत्या हो रही थी और बहन पार्टी में नाच रही थी। हत्यारोपी पुराने नौकर विशाल गौतम ने शालू के कहने पर वारदात करने की बात कही थी। अब पुलिस नए सिरे से जांच करेगी।

जयपुर में पति व 3 बेटियों की हत्या, पति फरार



जयपुर. एजेंसी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। करधनी थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके तीन बच्चों की हत्या हो गई। हत्या किसने की, इस फिलहाल साफ नहीं है। महिला का पति राहुल झा मौके पर नहीं है। ऐसे में राहुल संदेह के घेरे में है। दरअसल, घटना हाथोज गांव में स्थित स्कॉलर्स इंटरनेशनल स्कूल के पास की बताई जा रही है। गोविंद वाटिका के मकान- ए 169 में ये हत्याएं हुई हैं। मकान राहुल झा नाम है। घर में राहुल के पिता मौजूद हैं, पर वह गायब है। बताते हैं, महिला और तीन बच्चों की हत्या सीमेंट के ब्लॉक से कूचकर कर दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

बंगाल के पूर्व राज्यपाल बोस की Z+ सुरक्षा जारी रहेगी कोलकाता. एजेंसी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल के पूर्व राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस की जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा जारी रखने का निर्णय लिया है। बोस के एक करीबी सूत्र ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। हालांकि, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में थोड़ा बदलाव किया गया है। अब दिल्ली पुलिस उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। डॉ. बोस फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) उन्हें पूरे देश में सुरक्षा प्रदान कर रही थी। सूत्र ने बताया कि वह मंत्रालय में हाल में दिल्ली में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में विभिन्न प्रमुख व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जा रही केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। इसी दौरान बंगाल के पूर्व राज्यपाल डा. आनंद बोस की सुरक्षा जारी रखने का फैसला किया गया। उनके लिए जेड प्लस श्रेणी का सुरक्षा कवर बककरार रहेगा। मौलूम हो कि बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पांच मार्च 2026 को डा. सीवी आनंद बोस ने बंगाल के राज्यपाल पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था। हालांकि राज्यपाल के पद से हटने के बाद भी केंद्र सरकार ने उनके लिए उच्च श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था जारी रखी है।

शिक्षक की परीक्षा लीजिए, पर पहले व्यवस्था की भी लीजिए

एकीकृत शिक्षक संघ के अध्यक्ष रणजीत मीणा भी यही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षकों से अपेक्षाएं रखने के साथ उन पर लंदे काम के बोझ की चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। नए शिक्षकों की पात्रता जांच के लिए परीक्षा हो, यह समझ में आता है, लेकिन वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के मामले में अनुभव और प्रशिक्षण को भी महत्व मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता स्पष्ट कर दिया है। अब गंद राज्य सरकार के पाले में है कि वह फैसले को कैसे लागू करती है। मप्र में फिलहाल टीईटी की आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और परीक्षा अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित है। इसलिए अब

बहस यह नहीं हो सकती कि कोर्ट के फैसले को माना जाए या नहीं। बहस यह होनी चाहिए कि फैसले का पालन कर उन हजारों शिक्षकों के साथ न्याय कैसे हो, जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सरकारी स्कूलों और बच्चों को दिया है।

शिक्षक की परीक्षा जरूर लीजिए, लेकिन उससे पहले उस व्यवस्था की परीक्षा तो लीजिए जिसमें उसे पढ़ाना है। क्योंकि किसी शिक्षक की काबिलियत सिर्फ एक परीक्षा की उतर पुस्तिका में नहीं होती। वह वर्षों के अनुभव, प्रशिक्षण, पढ़ाए हुए बच्चों व रोज की कठिन परिस्थितियों में दिखती है।

के दौरान नई प्रणालियों को लेकर प्रशिक्षण की व्यवस्था मौजूद है। मप्र एससीईआरटी की संरचना में भी शिक्षक-शिक्षा का अलग विंग है। यानी सरकार खुद मानती है कि शिक्षक को बदलती शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप लगातार प्रशिक्षित और अपडेट किए जाने की जरूरत है। शिक्षक की इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से गुजरते हैं। फिर सवाल यह है कि जिस शिक्षक को सरकार साल-दर-साल नई शिक्षा पद्धति में प्रशिक्षित कर रही है, उसकी वर्षों की सेवा, अनुभव व प्रशिक्षण का मूल्यांकन किस रूप में किया जा रहा है? टीईटी को लेकर बहस यहीं से शुरू होती है... मप्र के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिनके पास शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, स्नातक या उससे उच्च स्तर की शैक्षणिक योग्यता है। नियमित शिक्षक चयन प्रक्रिया

से गुजरकर सेवा में आए हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अलग है, लेकिन वे भी वर्षों से पढ़ा रहे हैं। ऐसे में किसी शिक्षक से वर्षों की सेवा लेने के बाद यह कहना कि अब एक और पात्रता परीक्षा देकर योग्यता साबित करो, सवाल पैदा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी कसौटी पर टीईटी की अनिवार्यता कायम रखी है, लेकिन क्या राज्य सरकार इस व्यवस्था को लागू करते समय अनुभव, प्रशिक्षण और वास्तविक कार्य-परिस्थितियों का भी संज्ञान ले सकती है? यह सवाल अभी भी पूछा जा सकता है। कर्नाटक में भी इन-सर्विस शिक्षकों पर टीईटी अनिवार्य किए जाने का विरोध सामने आया है और इसे वापस लेने की मांग की गई। जम्मू-कश्मीर में मामला और दिलचस्प है। वहां सरकार ने फरवरी में टीईटी के लिए दो संस्थाओं को नोडल एजेंसी बनाया

था, लेकिन शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने बाद में परीक्षा को फिलहाल रोकने और मामले पर व्यापक विचार करने की बात कही। यानी वहां भी सरकार व शिक्षकों के बीच इस फैसले को लागू करने के तरीके को लेकर असमंजस और पुनर्विचार की स्थिति है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश ने पुराने इन-सर्विस शिक्षकों के लिए अलग विशेष आयोजित करने का रास्ता निकाला है। यानी देश के अलग-अलग हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन का तरीका भी अलग-अलग तलाशा जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी क्या ऐसा कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं निकाला जा सकता? शिक्षा विभाग के सूत्रों की माने तो इसकी कवायद चल रही है, लेकिन अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। शिक्षकों की चुनौतियां टेड तक सीमित नहीं: दरअसल शिक्षक की समस्या सिर्फ टीईटी तक सीमित नहीं है। एक शिक्षक ने नाम न छापने की शर्त पर अपनी पीड़ा कुछ यूँ व्यक्त की - मप्र में गुरुजनों की हालत मंदिर के उस घंटे जैसी हो गई है, जिसे कोई भी आकर बजा जाता है। कभी जनगणना, कभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण, कभी सरकारी योजनाओं की जानकारी, कभी सर्वेक्षण और कभी दूसरे काम। शिक्षक का मूल काम बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन उसके हिस्से में सरकारी मशीनरी के कई दूसरे काम भी आते रहे हैं। फिर ई-अटेंडेंस है। मोबाइल नेटवर्क नहीं है तो शिक्षक सीडियों या छत पर जाकर नेटवर्क तलाशता है। स्कूलों में शौचालय हैं लेकिन नियमित सफाई व्यवस्था नहीं। कई ग्रामीण स्कूलों में पानी की

समस्या भी है। स्कूलों में बच्चों से कहीं सफाई करवाना होता है तो जांच होनी चाहिए। लेकिन यह मान लेना कि शिक्षक जाति या धर्म के आधार पर बच्चों से झाड़ू लगवाते हैं, पूरी तस्वीर नहीं है। जहां सफाईकर्मी नहीं हैं, वहां कई बार शिक्षक भी सफाई करते हैं। और असली सवाल फिर वहीं लौटता है... इन तमाम गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियों के बाद शिक्षक को पढ़ाने के लिए वास्तविक समय कितना बचता है? राज्य शिक्षा केंद्र से आने वाली विभिन्न प्रश्नावलियां, आंकड़ों का संकलन, ऑनलाइन प्रविष्टियां और अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करने का काम भी शिक्षकों को करना पड़ता है। कई स्कूलों में बाबू या डाटा एंट्री ऑपरेटर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नतीजा यह कि शिक्षक कभी शिक्षक, कभी लिपिक और कभी डाकिये की भूमिका निभाता दिखाई देता है। इसके बाद भी उससे अपेक्षा की जाती है कि बच्चों के परिणाम शानदार हों। बिस्कुल होनी चाहिए। शिक्षक की जवाबदेही भी होनी चाहिए। लेकिन जवाबदेही के साथ व्यवस्था की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। जिस शिक्षक को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता पहले से निर्धारित है, जो वर्षों से कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा है और जिसके काम का मूल्यांकन परीक्षा परिणामों तथा विभागीय निरीक्षणों से होता है, उसके लिए टीईटी को किस तरह लागू किया जाए, यह सरकार को संवेदनशीलता से तय करना चाहिए।

नौसेना और तटरक्षक के लिए सतह और अंडरवाटर पोत बनाएगी कंपनी रक्षा क्षेत्र में बड़ी कामयाबी, सागर डिफेंस को मिला सैन्य जलपोत बनाने का लाइसेंस

नई दिल्ली। एजेंसी महाराष्ट्र के डीप-टेक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग लिमिटेड ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सरकार ने कंपनी को सैन्य उपयोग के लिए सतह और पानी के भीतर काम करने वाले अंडरवाटर पोतों के निर्माण का आधिकारिक औद्योगिक लाइसेंस दे दिया है। इस लाइसेंस के बाद कंपनी भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के लिए रक्षा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकेगी। यह स्टार्टअप नौसेना के लिए जहाज बनाने का लाइसेंस पाने वाली चुनिंदा निजी कंपनियों में शामिल हो गया है। नए लाइसेंस के तहत कंपनी निर्दिष्ट नौसैनिक रक्षा प्लेटफार्म, संबंधित प्रणालियों का डिजाइन, निर्माण, एकीकरण, असेंबली, परीक्षण और आपूर्ति करेगी। इससे पहले इसी साल कंपनी को हथियार, विस्फोटक और गोला-बारूद निर्माण का भी लाइसेंस मिल चुका है। कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष कैप्टन निकुंज पराशर ने इसे महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि यह लाइसेंस रणनीतिक परियोजनाओं में भागीदारी की क्षमता को मजबूत करेगा। उद्योग सूत्रों के मुताबिक यह कदम रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम है। कंपनी शुरू से ही समुद्री और मानवरहित प्रणालियों के विकास से जुड़ी है और रक्षा व वाणिज्यिक दोनों क्षेत्रों के लिए स्वायत्त समुद्री और हवाई प्रणालियां बनाती है।



हथियार से लेकर अंडरवाटर सिस्टम तक पहुंच

कंपनी के लिए यह दूसरा बड़ा लाइसेंस है। इसी साल की शुरुआत में उसे हथियार, विस्फोटक और गोला-बारूद बनाने का औद्योगिक लाइसेंस मिला था, जो अलग श्रेणी का है। अब सतह और अंडरवाटर पोतों का लाइसेंस मिलने से कंपनी का पोर्टफोलियो और मजबूत हो गया है। सागर डिफेंस स्वायत्त और मानवरहित समुद्री और हवाई प्रणालियों में विशेषज्ञता रखती है, जो भविष्य के युद्ध में निर्णायक मानी जा रही हैं। कैप्टन निकुंज पराशर ने कहा कि यह लाइसेंस कंपनी को रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में बड़ी भूमिका निभाने का मौका देगा। विशेषज्ञों का मानना ​​है कि इससे भारत के रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को गति मिलेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। स्वदेशी तकनीक से बने सतह और अंडरवाटर प्लेटफॉर्म नौसेना की ताकत बढ़ाएंगे। यह उपलब्धि डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए भी प्रेरणा है कि वे रक्षा क्षेत्र में बड़े अवसर तलाश सकते हैं।

सीएम शुभेंदु ने गिरफ्तारी का दिया निर्देश बागेश्वर बाबा की तस्वीरें जलाने वालों पर की जाएगी कार्रवाई

कोलकाता। एजेंसी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा की तस्वीरें जलाने वालों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। मालूम हो कि बागेश्वर बाबा ने अपने बंगाल दौरे के दौरान दुर्गापूजा और नवरात्रि में बंगाल के हिंदुओं से मांसाहार और मदिरा छोड़ने की अपील की थी। उन्होंने धार्मिक आयोजनों और पूजा पंडालों के पास मांस-मछली खाने



और बेचने वालों को पारखंडी और ढोंगी कह दिया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। उनके खिलाफ थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। कोलकाता के भवानीपुर थाने के सामने बागेश्वर बाबा की तस्वीरें भी जलाई गईं। प्रदर्शनकारियों ने इसे बंगाली खान-पान, पहचान और संस्कृति के विरुद्ध टिप्पणी करार दिया। प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल थे।

मेट्रो एंकर

महाराष्ट्र में महामासाद, भंडारा और लंगर से पहले पोर्टल पर देनी होगी जानकारी

खाना परोसने से 7 दिन पहले सूचना दें आयोजक, एफडीए ने लागू किया नया नियम

मंबई। एजेंसी महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान लाखों श्रद्धालुओं को महामासाद, प्रसाद परोसा जाएगा। इसे देखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने नया नियम लागू किया है। इसके तहत त्योहारों, धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को कार्यक्रम से कम से कम सात दिन पहले एफडीए के फूड एंड ड्रग ग्रीवेंस पोर्टल के जरिए तयशुदा सामूहिक भोजन वितरण की पूर्व-सूचना फार्म संबंधित अधिकारी के पास जमा करना होगा। यह नियम उन आयोजकों के लिए होगा जहां महामासाद, लंगर, भंडारा या बड़े पैमाने पर भोजन वितरण होते हैं। एफडीए ने कहा कि पहले से जानकारी मिलने पर जोखिम के आधार पर जांच करने, खाने के सैंपल इकट्ठा करने और जहां भी जरूरत हो, तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जहां खाना किसी लाइसेंस-

नीचे मछली, ऊपर बिजली: तालाब में सोलर प्लांट से ऊर्जा और किसानों को रोजगार

सुपौल (बिहार)। एजेंसी बिहार के सुपौल जिले में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ सखुआ गांव में राजा पोखर में 525 किलोवाट पीक क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर पावर लगाया गया है। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इसकी नींव रखी थी। इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि बिजली के साथ यहां मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली की अवधारणा को प्रभावी रूप से लागू



करने पर जोर दिया गया है। यहां वैज्ञानिक तरीके से मत्स्य पालन की गतिविधियां शुरू कराने की कवायद की जा रही है।

इस प्लांट से रोजाना 700-800 यूनिट बिजली का उत्पादन भी हो रहा है। इसे बढ़ाकर 2400 यूनिट करने का लक्ष्य है।

सरकार का दावा है कि इस व्यवस्था से स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उनकी आय बढ़ेगी।